▸▸वर्ष : 34 ▸▸अंक : 344 ▸▸मुंबई, शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 ▸▸RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸मूल्य : 3 रुपए ▸▸epaper.dobajedopahar.com ▸▸संपादक : अरुण लाल ▸▸संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज से

काउंटडाउन खत्म

16 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल

'कॉपीमुक्त अभियान' के लिए 271 भरारी पथक तैनात

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है। इस बार 16 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी और बोर्ड ने इस बार अतिरिक्त पढ़ने का समय भी खत्म कर दिया है। साथ ही छात्रों के लिए सख्त नियम भी जारी किए गए हैं।

16,15,489 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया

18 मार्च तक आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं (SSC) की बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल कुल 16,15,489 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। राज्य परीक्षा मंडल के सचिव दीपक माली ने जानकारी दी है कि परीक्षा को पूरी तरह 'कॉपीमुक्त' बनाने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस साल 23,683 स्कूलों से छात्रों का पंजीकरण हुआ है, जिनमें 8,65,740 छात्र, 7,49,736 छात्राएं, 13 ट्रांसजेंडर और 9,788 दिव्यांग विद्यार्थी शामिल हैं।

कॉपी करने में मदद करने वाले कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

परीक्षा मंडल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी या शिक्षक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को कॉपी करने में मदद करते हुए पाया गया, तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड का लक्ष्य परीक्षा की पारदर्शिता और गरिमा को बनाए रखना है, जिसके लिए सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षकों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यभर में सुचारू और पारदर्शक परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'कॉपीमुक्त अभियान' के तहत 271 भरारी पथक (फ्लाइंग स्क्वायड) नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, जिलाधिकारियों को अपने जिले की आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर नियोजन करने की पूरी छूट दी गई है। बोर्ड का प्रयास है कि किसी भी केंद्र पर अनुचित साधनों का उपयोग न हो सके।

अनुपस्थित छात्रों के लिए मार्च के अंत में दोबारा अवसर

बोर्ड ने उन विद्यार्थियों के लिए राहत की घोषणा की है जो किसी चिकित्सा (मेडिकल) समस्या या अनिवार्य कारणों से अपनी प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) या मौखिक परीक्षा नहीं दे पाए हैं। ऐसे विद्यार्थी 20 से 24 मार्च 2026 के बीच अपनी बकाया परीक्षा दे सकेंगे। इससे छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने से बच सकेगा।

मुंबई मंडल में सर्वाधिक छात्र, कोंकण में सबसे कम

परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का विभागवार विवरण भी जारी किया गया है। मुंबई विभाग में सबसे अधिक 3,49,873 छात्र परीक्षा देंगे, जबकि कोंकण विभाग में सबसे कम 25,779 छात्र शामिल होंगे। अन्य प्रमुख विभागों में पुणे (2.78 लाख), नासिक (2.06 लाख) और छत्रपति संभाजीनगर (1.91 लाख) शामिल हैं।

12वीं की परीक्षा में नकल के मामलों ने बढ़ाई चिंता

बोर्ड सचिव दीपक माली ने बताया कि चल रही 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान मुंबई विभाग में नकल के 10 मामले सामने आए हैं। बुधवार को हुए रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) के पेपर में 8 और राजनीति विज्ञान के पेपर में 2 मामले दर्ज किए गए। पूरे राज्य की बात करें तो रसायन विज्ञान में 67 और राजनीति विज्ञान में 7 अनुचित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन 10वीं की परीक्षा को लेकर और अधिक सतर्क हो गया है।

एसआईआर की अब पूरे देश में तैयारी

एजेंसी । नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने गुरुवार को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर लिखकर SIR से जुड़ी तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है।

चुनाव आयोग ने दिल्ली-कर्नाटक समेत 22 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में की एसआईआर की घोषणा

▸▸अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया

▸▸अभी 12 राज्यों में वोटर्स वेरिफिकेशन जारी

क्या कहा निर्वाचन आयोग ने?

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होगा। आयोग ने राज्यों से इससे संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) इसके दायरे में आ जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस अभ्यास के पूरा होने के बाद देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।

बिहार में यह प्रक्रिया पूरी

चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में यह जारी है। वहीं असम में एसआईआर के बजाय 'स्पेशल रिवीजन' प्रक्रिया 10 फरवरी को पूरी कर ली गई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के अखिल भारतीय एसआईआर का आदेश पिछले साल जून में दिया गया था।

एसआईआर में क्या-क्या किया जाएगा?

उन्होंने बताया कि हर घर पर बीएलओ तीन बार जाएंगे और मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान बीएलओ की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी योग्य मतदाता इस अभियान न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता नहीं जुड़े। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है, वहां आज रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

क्या है एसआईआर का उद्देश्य?

विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार करना और इसमें नए मतदाताओं का समावेश करना है। इसमें नामों की जांच, पुराने मतदाताओं की पुष्टि, और आवश्यक संशोधन शामिल होंगे। आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर कर नए मतदाताओं को शामिल किया जाएगा।

2026 में इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव

बता दें कि देश के पांच राज्यों में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हालांकि, जिन राज्यों में इस समय स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं, वहां फिलहाल यह प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि स्थानीय स्तर का प्रशासन चुनावी कामकाज में व्यस्त रहेगा।

एयरपोर्ट पर गांजे का 'जखीरा'

24 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, छह गिरफ्तार

एजेंसी । नई दिल्ली

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने पिछले सात दिनों के भीतर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग मामलों में सघन जांच करते हुए अधिकारियों ने कुल 24 किलोग्राम 'हाइड्रोपोनिक गांजा' जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 24.3 करोड़ रुपये है। इस मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए सभी आरोपी बैंकॉक से उड़ान भरकर मुंबई पहुंचे थे।

खुफिया जानकारी और प्रोफाइलिंग से खुला तस्करी का राज

कस्टम आयुक्तालय ने तस्करी के इन मामलों को पकड़ने के लिए 'उन्नत यात्री सूचना प्रणाली' (APIS) और यात्रियों की प्रोफाइलिंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इसी के आधार पर शुरुआती तीन मामलों का खुलासा हुआ, जिनमें 9.5 करोड़ रुपये मूल्य का 9.5 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। वहीं, बाकी के तीन मामलों में आरोपियों को विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर धर दबोचा गया। जांच में यह बात सामने आई कि हर मामले में तस्करों ने इस महंगे हाइड्रोपोनिक गांजे को जांच से बचाने के लिए अपने ट्रॉली बैग के अंदर बड़ी चालाकी से छिपा रखा था।

कपड़ों में छिपाकर लाया जा रहा 1.85 करोड़ का सोना भी बरामद

ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ने के अलावा, कस्टम अधिकारियों ने सोने की तस्करी के खिलाफ भी सफल कार्रवाई की है। हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान तीन अन्य यात्रियों के पास से 1.3 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। पकड़े गए इस अवैध सोने की कीमत लगभग 1.85 करोड़ रुपये आंकी गई है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि शातिर आरोपियों ने एयरपोर्ट की सुरक्षा और स्कैनिंग से बचने के लिए इस सोने को अपने पहने हुए कपड़ों के अंदर छिपाकर रखा था।

ब्रीफ न्यूज़

23 साल की नौकरी के बाद अमृता फडणवीस का इस्तीफा

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने बैंकिंग क्षेत्र में 23 साल के लंबे सफर के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को साझा करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने एक्सिस बैंक में अपनी सेवा पूरी कर ली है। अमृता ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी की थी और वह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जैसे प्रतिष्ठित पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। अपने विदाई संदेश में उन्होंने बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी सहित अपने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है।

प्लेन क्रैश : 26-27 फरवरी तक आ सकती है शुरुआती जांच रिपोर्ट

मुंबई\नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों को ले जा रहे लीयरजेट 45 (VT-SSK) प्लेन क्रैश मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट घटना के 30 दिनों के अंदर जारी की जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय ने यह दावा करते हुए कहा कि प्लेन क्रैश 28 जनवरी को हुआ था। इस हिसाब से इस मामले में शुरुआती जांच रिपोर्ट 26-27 फरवरी तक जारी कर दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि प्लेन में दो फ्लाइट रिकॉर्डर लगे थे। इनमें एक L3 कम्युनिकेशंस द्वारा निर्मित 'डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर' (DFDR) था। जिसका डेटा नई दिल्ली स्थित AAIB की लैब में डाउनलोड कर लिया गया है। लेकिन आग की वजह से डैमेज हुए 'कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर' (CVR) का डेटा अभी तक नहीं निकल सका है। यह हनीवेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसके लिए इसी विदेशी कंपनी की मदद भी मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद इस तरह की छोटी एयरलाइंस वाली तमाम कंपनियों के सिक्योरिटी ऑडिट भी किए जा रहे हैं।

खत्म नहीं हो रही मुंडे की मुश्किलें

▸▸मनोज जरांगे ने धनंजय मुंडे पर लगाया 17 लाख रुपये घूस लेने का आरोप

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल मचा दी है। उन्होंने रंजना नागपूरकर नामक एक महिला के गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए दावा किया है कि एक मामले में अनुकूल फैसला दिलाने के एवज में धनंजय मुंडे को 17 लाख रुपये दिए गए थे। महिला के पति प्रदीप नागपूरकर पुलिस विभाग में कार्यरत थे। आरोप है कि पैसे देने के बावजूद काम नहीं हुआ, जिससे परिवार पर भारी आर्थिक और मानसिक दबाव पड़ा। महिला का दावा है कि इसी भारी तनाव के चलते उनके पति की दुखद मृत्यु हो गई। इस खुलासे के बाद जरांगे ने पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मुख्यमंत्री फडणवीस के रिश्तेदार से जुड़े हैं तार

मनोज जरांगे ने इस मामले में एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यह पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है। हालांकि, जरांगे ने यह भी स्पष्ट किया कि संभव है कि मुख्यमंत्री को इस पूरे लेन-देन और मामले की कोई जानकारी न हो। लेकिन मामला सीधे उनके निकट संबंधियों से जुड़ा होने के कारण, यह जरूरी हो जाता है कि सरकार इस मामले का संज्ञान ले और पूरी संवेदनशीलता के साथ इसमें हस्तक्षेप करे ताकि सच्चाई सामने आ सके।

तकनीकी शिक्षकों की निकल पड़ी

▸▸प्रमोशन के लिए पीएचडी की शर्त खत्म, सीएएस नियमों में ढील

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय (DTE) के अधीन आने वाले सरकारी और सहायता प्राप्त डिप्लोमा एवं डिग्री संस्थानों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम' (CAS) के तहत पदोन्नति और उच्च वेतनमान से जुड़ी कई पात्रता शर्तों में काफी हद तक ढील देने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। अधिकारियों द्वारा गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले से विशेष रूप से उन व्याख्याताओं (लेक्चरर्स) को सीधा फायदा होगा, जो पहले संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) या अस्थायी पदों पर नियुक्त थे और बाद में सरकार द्वारा उन्हें नियमित कर दिया गया। नए आदेश के तहत, यह सुनिश्चित किया गया है कि इन शिक्षकों को CAS का लाभ पहले की तरह ही प्रदान किया जाए। इसके साथ ही, इन व्याख्याताओं को अपना अनिवार्य 'रिफ्रेशर कोर्स' पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया था, जिसे मान्य रखा गया है।

2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म

इस फैसले की सबसे अहम घोषणाओं में से एक पीएचडी (PhD) की अनिवार्यता को खत्म करना है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5 मार्च 2010 से पहले नियुक्त किए गए व्याख्याताओं को CAS के तहत उच्च वेतनमान या पदोन्नति पाने के लिए अब पीएचडी होना अनिवार्य नहीं होगा। बुधवार को जारी किए गए एक आधिकारिक सरकारी आदेश के जरिए शैक्षणिक, प्रशिक्षण और योग्यता संबंधी इन नई छूटों को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण (MAT) के आदेश के बाद उठाया गया कदम

राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव का यह महत्वपूर्ण कदम महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (MAT) के 7 फरवरी 2025 के आदेश के बाद उठाया है। दरअसल, कई व्याख्याताओं ने जून 2022 में जारी किए गए सरकारी संकल्प (GR) और पदोन्नति नियमों से जुड़े एक संबंधित परिपत्र को न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने शिक्षकों की इन याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विवादित परिपत्र को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा।

ट्रंप का करीबी था एपस्टीन, नाबालिग लड़कियों की तस्करी का था बड़ा नेटवर्क

एपस्टीन फाइल्स में फंसी दुनिया की दिग्गज हस्तियां

एजेंसी । वाशिंगटन

जेफरी एपस्टीन से संबंधों के शक में ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय के भाई को गिरफ्तार किया गया है। जेफरी एपस्टीन फाइनेंसर था। उस पर कम उम्र की लड़कियों का एक बड़ा नेटवर्क चलाने का आरोप था। इस फाइल में दुनिया के दिग्गजों के नाम शामिल हैं।

एपस्टीन फाइल्स में क्या शामिल है?

दस्तावेजों के इस जत्थे में अदालती दस्तावेज, बयान, पीड़ितों की गवाही, ईमेल, फ्लाइट लॉग, संपर्क सूचियां, फोटो और वीडियो शामिल हैं। एफबीआई की जांच के इन दस्तावेजों में करीब 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो हैं, जिनमें विभिन्न सामाजिक समारोहों में कई प्रभावशाली लोगों की तस्वीरें शामिल हैं।

कौन था जेफरी एपस्टीन?

न्यूयॉर्क में जन्मे और पले-बढ़े एपस्टीन ने 1970 के दशक के बीच में शहर के प्राइवेट डाल्टन स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया। हालांकि वे कभी ग्रेजुएट नहीं हुए। कहा जाता है कि उनके एक स्टूडेंट के पिता इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एपस्टीन का संपर्क वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स के एक सीनियर पार्टनर से करवाया। वह चार साल के अंदर वहां पार्टनर बन गए। 1982 तक, उन्होंने अपनी खुद की फर्म, जे एपस्टीन एंड कंपनी बना ली थी। एपस्टीन ने जल्द ही सेलिब्रिटीज, कलाकारों और राजनीतिज्ञों के साथ मिलना-जुलना शुरू कर दिया।

2005 में खुला मामला

एपस्टीन के खिलाफ 2005 में, एक 14 साल की लड़की के माता-पिता ने फ्लोरिडा में पुलिस को बताया कि एपस्टीन ने अपने पाम बीच वाले घर पर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो पूरे घर में लड़कियों की तस्वीरें मिलीं। इसी मामले में एपस्टीन को पहली बार जुलाई 2006 में गिरफ्तार किया गया था। 2008 में एक विवादास्पद डील के बाद उसे सिर्फ 18 महीने की जेल हुई। दूसरी बार उसे जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क के संघीय अभियोजकों ने उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग (नाबालिग लड़कियों की तस्करी) और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए थे।

ट्रंप ने चुनाव में फाइलें जारी करने का वादा किया था

2024 के अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एपस्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करना अच्छा विचार होगा। 18 नवंबर, 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बहुमत से 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' पारित किया और ट्रंप ने अगले ही दिन इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। जिसके बाद जस्टिस डिपार्टमेंट को 19 दिसंबर तक एपस्टीन के खिलाफ हुई क्रिमिनल जांच से जुड़ी अपनी सभी फाइलें जारी करने का आदेश दिया।

सियासी मोलभाव शुरू

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बहाने महाविकास आघाड़ी (MVA) के भीतर सीटों के सौदेबाजी की राजनीति गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह राज्यसभा के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में पार्टी आगामी विधान परिषद चुनाव में अपने लिए एक सीट चाहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटील ने स्पष्ट किया कि पार्टी के स्थानीय और दिल्ली के नेता चाहते हैं कि शरद गुट को समर्थन देते समय 'सम्मानजनक हिस्सेदारी' तय की जाए।

राज्यसभा में समर्थन के बदले कांग्रेस ने मांगी विधान परिषद की सीट

राज्य समेत पूरे देश में अगली जनगणना पूरी तरह होगी डिजिटल

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

भारत की आगामी जनगणना अब पारंपरिक कागजी प्रपत्रों के बजाय पूरी तरह डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी। महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने 'जनगणना 2027' के संदर्भ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में इसका आधिकारिक आह्वान किया। सह्याद्री अतिथि गृह में हुई इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग इस प्रक्रिया को पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अभी से कमर कस लें। वर्ष 2011 के बाद, 16 वर्षों के लंबे अंतराल पर होने वाली यह जनगणना देश के भविष्य के लिए विशेष महत्व रखती है।

तकनीक और पारदर्शिता से सशक्त होंगे सरकारी आंकड़े

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि जनगणना 2027 तकनीक पर आधारित होगी, जिससे आंकड़ों में त्रुटियों की संभावना कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इन डिजिटल आंकड़ों का उपयोग आयुष्मान भारत जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सटीक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में विभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और महानगरपालिका आयुक्तों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि डेटा संकलन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा व्यास के अनुसार, महाराष्ट्र में जनगणना की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी, जिसके लिए राज्य के लगभग 2.64 लाख कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कर्मचारी घर-घर जाकर मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से डिजिटल एंट्री करेंगे, जिससे डेटा संकलन में होने वाला विलंब समाप्त हो जाएगा।

72 हजार से अधिक झोपड़ीधारकों को मिलेगा घर

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

सर्वे और बायोमेट्रिक प्रक्रिया शुरू

बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले करीब 72,665 झोपड़ीधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही बेलापुर, नेरुल और तुर्भे इलाके के झोपड़ीधारकों को उनके हक का पक्का घर मिलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भाजपा विधायक मंदा म्हात्रे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र झोपड़ीधारकों को मुफ्त घर दिया जाएगा, जबकि अपात्र माने जाने वाले लोगों को एक तय राशि का भुगतान करके घर उपलब्ध कराया जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित योजना के शुरू होने से स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर है।

नागरिकों के लिए लगेगा विशेष मार्गदर्शन शिविर

विधायक मंदा म्हात्रे ने बेलापुर विधानसभा के लोगों से अपील की है कि इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी, दस्तावेज या मार्गदर्शन के लिए वे बेझिझक उनके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए जल्द ही एक बड़ा मार्गदर्शन शिविर भी आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में गृहनिर्माण विभाग के अधिकारियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे मौके पर ही लोगों की शंकाओं का समाधान कर सकें।

पात्रता की शर्तें

झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत घर के मालिकाना हक के लिए समय-सीमा (कट-ऑफ) तय कर दी गई है। नई व्यवस्था के अनुसार, जिन लोगों की झोपड़ियां वर्ष 2000 से पहले की हैं, उन्हें पूरी तरह से मुफ्त में घर का मालिकाना हक सौंपा जाएगा। वहीं, जो झोपड़ीधारक वर्ष 2000 से लेकर 2011 के बीच बसे हैं, उन्हें 2,50,000 की मामूली राशि जमा करने पर पक्के घर का मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा।

मंत्री के निर्देश और बायोमेट्रिक सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेजी

गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर के कार्यालय में आयोजित एक अहम बैठक में इस पुनर्वसन परियोजना को तेजी से लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैठक में लंबित प्रस्तावों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तुरंत GBR प्रक्रिया के तहत सर्वेक्षण, DSR तैयार करने और बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू करने को कहा गया है। वर्तमान में तुर्भे के शिवाजी नगर इलाके में यह प्रक्रिया 3C चरण तक पहुंच गई है और शासन के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है।

शादी का झांसा देकर लूटी आबरू

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

मेट्रिमोनियल साइट पर हुई मुलाकात, 12 लाख रुपये ठगने का आरोप

मजबूरी का बहाना बनाकर ऐंठे करीब 12 लाख रुपए

कामोठे इलाके में एक 32 वर्षीय महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और लगभग 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कामोठे पुलिस ने पनवेल के कारंजड़े इलाके में रहने वाले 33 वर्षीय आरोपी अक्षय रंगराव पाटील को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला और आरोपी दोनों ही तलाकशुदा हैं। उन दोनों ने दूसरी शादी के लिए एक मेट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इसी वेबसाइट के जरिए नवंबर 2025 में आरोपी ने महिला से संपर्क किया और उससे शादी की इच्छा जताई। धीरे-धीरे उसने महिला को अपने विश्वास में ले लिया और शिकायत के अनुसार, शादी का झूठा वादा करके उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक शोषण के साथ-साथ आरोपी ने महिला का आर्थिक शोषण भी किया। उसने खुद को व्यावसायिक और आर्थिक संकट में बताकर महिला से कई बार पैसे मांगे। बात यहीं तक नहीं रुकी, उसने महिला को कर्ज लेने के लिए भी मजबूर किया। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने इस तरह कुल 11 लाख 92 हजार 900 रुपए की ठगी की। जब महिला को अपने साथ हो रहे धोखे का एहसास हुआ, तो उसने कामोठे पुलिस स्टेशन का रुख किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है।

कंप्यूटर हैक करके बैंक खाते से उड़ाए 16.50 लाख

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज

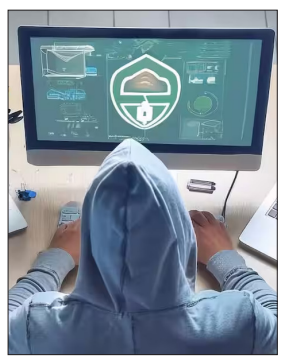

शहर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 16.50 लाख रुपए की ठगी का एक बड़ा साइबर अपराध सामने आया है। इस घटना के बाद से स्थानीय व्यवसायियों और व्यापारियों में डर का माहौल बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना पद्मनगर इलाके में स्थित 'श्री सरस्वती इजी रिचार्ज सर्विसेज प्रा. लि.' के साथ हुई है। 13 जनवरी 2026 की दोपहर जब कंपनी के संचालक संजीव रंगय्या अंकम (35) अपने कार्यालय में थे, तब उनकी कंपनी के महेश सहकारी बैंक लिमिटेड के खाते में आरटीजीएस (RTGS) के जरिए 28,56,740 रुपए आए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात हैकर ने कंप्यूटर और डिजिटल साधनों का इस्तेमाल कर एक फर्जी पहचान बनाई और कंपनी के खाते से 16,50,000 रुपए की बड़ी रकम ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। बैंक स्टेटमेंट चेक करने पर संचालक को इस हेराफेरी का पता चला।

डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू, पुलिस की सतर्क रहने की अपील

ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने तुरंत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन का रुख किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) 2000 की धारा 66-डी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस उपनिरीक्षक ललित केदारे बैंक के लेन-देन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को खंगाल रहे हैं ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। इसके साथ ही, पुलिस ने सभी नागरिकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय पूरी तरह सतर्क रहें।

टोइंग गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

नासिक-मुंबई हाईवे पर मंगलवार शाम एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार टोइंग वैन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में बाइक चला रहे 32 वर्षीय प्रताप सुरेश यादव की जान चली गई। प्रताप ठाणे पूर्व के कोपरीगांव इलाके के रहने वाले थे। गंभीर रूप से घायल प्रताप को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रात करीब 8:25 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रताप अपने 30 वर्षीय दोस्त अक्षय आनंद सावंत (डोंबिवली निवासी) के साथ अपनी होंडा यूनिकॉर्न बाइक (MH-04 MS 0609) से घर लौट रहे थे। शाम करीब 6:30 बजे जब वे मुंबई ढाबा के सामने पहुंचे, तभी लापरवाही और तेज गति से आ रही एक टोइंग वैन (MH 42 T 0672) ने उन्हें टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि यातायात नियमों को ताक पर रखकर यह भारी वाहन एक नाबालिग चला रहा था। हादसे के बाद वह घायल को कोई चिकित्सीय मदद दिए बिना ही मौके से फरार हो गया।

नारपोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश तेज

इस दुखद घटना को लेकर मृतक के पीछे बैठे उनके दोस्त अक्षय सावंत की शिकायत पर नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने फरार वैन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 106 (1), 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, 134 (अ)(ब) के तहत एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल, सहायक पुलिस निरीक्षक (API) योगेश काकड़ इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और फरार नाबालिग आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

'जय भवानी, जय शिवराय' से गूंज उठा शहर

डीबीडी संवाददाता । भाईंदर

मीरा-भाईंदर शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती बेहद हर्षोल्लास और गहरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर पूरा शहर 'जय भवानी, हर-हर महादेव' और 'जय शिवराय' के गगनभेदी जयघोष से गूंज उठा। शहर में मौजूद दोनों ऐतिहासिक किलों की दीवारों तक इस जश्न की गूंज महसूस की गई। जगह-जगह आयोजित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कारण पूरे शहर का माहौल पूरी तरह से भगवामय हो गया। मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (MBMC) द्वारा इस अवसर पर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जश्न की शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई थी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारकों को आकर्षक रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। मुख्य कार्यक्रम में घोड़बंदर स्थित महाराज की भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा पर महापौर डिंपल मेहता, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल और मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित कर अभिवादन किया। इसके अलावा, मनपा मुख्यालय के प्रांगण में स्थापित शिवाजी महाराज और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमाओं तथा मुख्यालय की दूसरी मंजिल पर रखे महाराज के तैलचित्र पर भी माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया।

'सुशासन, देशभक्ति और कुशल रणनीति के आदर्श थे महाराज'

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य हस्तियों ने महाराज के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने कहा कि देश के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी कुशल सैन्य रणनीतियों (विशेषकर छापामार युद्ध) और धार्मिक सहिष्णुता के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। वहीं, महापौर डिंपल मेहता ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय नौसेना के जनक और महान रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ई. में पश्चिम भारत में 'हिन्दवी स्वराज' की मजबूत नींव रखी थी। उन्होंने महाराज को राष्ट्रप्रेम और सुशासन का एक जीता-जागता और आदर्श उदाहरण बताया।

छूट के बाद भी रसूखदारों ने नहीं भरे टैक्स

डीबीडी संवाददाता । उल्हासनगर

अब मनपा करेगी कुर्क, नीलामी की तैयारी तेज!

उल्हासनगर महानगरपालिका (मनपा) की आय के मुख्य स्रोत 'हाऊस टैक्स' (संपत्ति कर) की वसूली में भारी कमी आने के कारण मनपा की आर्थिक स्थिति डगमगाती हुई नजर आ रही है। इस गिरती आर्थिक स्थिति और शहर के विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को गंभीरता से लेते हुए, आईएएस निगमायुक्त मनीषा आव्हाले ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हाऊस टैक्स विभाग की प्रमुख नीलम चंद्रकांत कदम को टैक्स के बकायेदारों से सख्ती से निपटने और बकाया राशि वसूलने के लिए कठोर कदम उठाने के स्पष्ट आदेश दिए हैं।

मनपा प्रशासन द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए बार-बार दंड में छूट देने वाली 'अभय योजना' लागू की गई और व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाए गए। इसके बावजूद, राजनीतिक पहुंच और रसूख रखने वाले कई लोगों ने अपना टैक्स जमा नहीं किया। आर्थिक अभाव के कारण जब मनपा के लिए शहर के विकास और अन्य जरूरी कार्यों को चलाना मुश्किल हो गया, तो प्रशासन को मजबूरन संपत्ति सील करने जैसी सख्त कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। इस जब्ती अभियान के शुरू होते ही शहर के बकायेदारों में हड़कंप मच गया है। निगमायुक्त के आदेशों का पालन करते हुए, टैक्स विभाग की प्रमुख नीलम कदम अपनी टीम के साथ 10 बकायेदारों के ठिकानों पर जब्ती की कार्रवाई करने पहुंचीं।

पकड़ा गया नशे का कारोबारी

213 कफ सिरप बोतलों के साथ था फरार

स्कूटी मालिक पर भी कार्रवाई की मांग

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी के मामले में शांतिनगर पुलिस ने एक अहम सफलता हासिल की है। पुलिस ने नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले युवक को घटना के तीन दिन बाद उसके घर से धर दबोचा है। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 1.40 लाख रुपए मूल्य की 213 कोडीनयुक्त (Codeine) कफ सिरप की बोतलें पहले ही जब्त कर ली थीं। इस अहम गिरफ्तारी के बाद पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खंगालने में जुट गई है।

यह घटना 15 फरवरी की सुबह करीब 9:45 बजे की है, जब आरोपी जाफर शेख एक टी.वी. एस. जुपिटर स्कूटी पर दो बॉक्स में कोडीन कफ सिरप लेकर अशोक नगर से नेहरू नगर की तरफ जा रहा था। गुप्त सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम ने अशोक नगर पोस्ट ऑफिस के पास उसे रोकने की कोशिश की, तो वह घबराकर स्कूटी और प्रतिबंधित सिरप से भरे बॉक्स वहीं छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 123, 275, 278 और एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी थी।

स्कूटी मालिक की भूमिका पर उठे सवाल

इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उस स्कूटी के मालिक पर भी कानूनी शिकंजा कसने की मांग जोर पकड़ रही है, जिसका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक, जब्त की गई स्कूटी कौसर मटके के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले की गहन जांच चल रही है और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर स्कूटी मालिक के खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नशे के बढ़ते अवैध कारोबार से स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश

भिवंडी के नेहरू नगर (वार्ड क्रमांक 15) क्षेत्र में लंबे समय से गांजा और कोडीनयुक्त सिरप जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इलाके में नशेड़ियों के बढ़ते जमावड़े के कारण महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। इस बिगड़ती स्थिति से परेशान होकर स्थानीय नागरिकों ने ठाणे पुलिस आयुक्त, भिवंडी परिमंडल-2 के पुलिस उपायुक्त और शहर पुलिस स्टेशन को लिखित शिकायत सौंपकर इलाके से इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है।

भिवंडी में मेयर-डिप्टी मेयर को लेकर सियासत

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

एक साथ आए कांग्रेस-एनसीपी और बागी भाजपा पार्षद

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी, एनसीपी (एसपी) के पार्षदों और भाजपा के बागी पार्षदों के एक समूह ने मिलकर एक 'सेक्युलर फ्रंट' बनाया है। यह फ्रंट ठाणे जिले के भिवंडी-निजामपुर नगर निगम (बीएनएमसी) में मेयर और डिप्टी मेयर के पद हासिल करने की कोशिश करेगा।

पत्रकारों से बातचीत में सपकाल ने बताया कि 15 जनवरी को हुए चुनाव में कांग्रेस 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसे एनसीपी (एसपी) के 12 पार्षदों का समर्थन मिला है। 90 सदस्यीय निगम में बहुमत के लिए उसे सिर्फ चार और पार्षदों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है और अपने वैचारिक रुख से समझौता नहीं किया है। उनके मुताबिक कुछ भाजपा पार्षद पार्टी छोड़कर इस सेक्युलर फ्रंट में शामिल हो गए हैं, जिससे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने का रास्ता आसान होगा।

भाजपा को सत्ता से बाहर रखने की है रणनीति

सपकाल ने बताया कि नारायण चौधरी और उनके साथियों ने भाजपा छोड़कर एक स्वतंत्र समूह बनाया और कांग्रेस-नेतृत्व वाले फ्रंट को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ पिछले 24 दिनों से बातचीत चल रही थी, जो अब सफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के पदों पर अंतिम फैसला लेने के लिए जल्द ही पार्टी पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। भाजपा को सत्ता से बाहर रखना कांग्रेस की स्पष्ट रणनीति है। वहीं, भिवंडी से एनसीपी (एसपी) के लोकसभा सांसद सुरेश म्हात्रे (बाल्या मामा) ने कहा कि कांग्रेस-एनसीपी (एसपी) सेक्युलर फ्रंट बनाने की कोशिश करीब 24 दिनों से चल रही थी। समाजवादी पार्टी से भी बात हुई थी, लेकिन उसने शिंदे गुट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के बागी पार्षदों के समर्थन से अब नगर निगम में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है।

ट्यूशन टीचर ने 8वीं की छात्रा को मारे 40 डंडे

पहाड़ा याद ना करने की दी सजा

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

गोठीवली गांव में एक ट्यूशन शिक्षिका द्वारा आठवीं कक्षा की छात्रा को बेहद बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा गणित के पहाड़े (Tables) याद नहीं कर पाई थी, जिससे नाराज होकर शिक्षिका रूपाली थवी ने उसे लकड़ी की स्टिक से कई बार मारा। इस मारपीट के कारण छात्रा के हाथ पर सूजन आ गई और लाल निशान पड़ गए। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है।

पीड़ित छात्रा पिछले पांच वर्षों से इसी ट्यूशन क्लास में पढ़ रही थी। परिजनों का आरोप है कि जब बच्ची पहाड़ा नहीं सुना पाई, तो शिक्षिका ने सजा के तौर पर उसके हाथ पर करीब 20 बार स्टिक से प्रहार किया। बच्ची को असहनीय दर्द होने पर परिजनों ने उसका एक्सरे भी करवाया। गनीमत रही कि हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया, लेकिन मारपीट की गंभीरता ने शिक्षक की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

रबाले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज

छात्रा की मां पूनम वडके ने इस घटना के संबंध में रबाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने पिटाई को लेकर शिक्षिका से सवाल किया, तो उसने सहानुभूति दिखाने के बजाय अड़ियल रुख अपनाते हुए कहा कि बच्ची पढ़ाई नहीं करती। शिक्षिका ने यह भी कह दिया कि यदि परिवार को परेशानी है, तो वे बच्ची को किसी दूसरी ट्यूशन में भेज दें। रबाले पुलिस के क्राइम पीआई श्याम वनसोडे ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ठाणे जिला बाल संरक्षण विभाग ने भी इस घटना में हस्तक्षेप किया है। पुलिस अब छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराने और ट्यूशन के अन्य विद्यार्थियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है।

मनसुख हिरेन हत्या मामला

आरोपी संतोष शेलार को नहीं मिली जमानत

मुंबई। विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक रखने और उसके बाद हुई मनसुख हिरन की हत्या के मामले में संतोष शेलार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शेलार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का कथित करीबी सहयोगी बताया जाता है। जून 2021 में गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे रिहा करने से मना कर दिया है।

सीसीटीवी फुटेज में मनसुख हिरन के साथ दिखा आरोपी

अदालत ने उन सीसीटीवी फुटेज को भी बेहद अहम माना जिसमें शेलार की मौजूदगी दर्ज है। फुटेज के अनुसार, शेलार उस टवेरा कार में दिखाई दे रहा है जिसमें मनसुख हिरन को आखिरी बार देखा गया था। साक्ष्यों के मुताबिक, कार के भीतर शेलार ठीक मनसुख हिरन के बगल में बैठा था। सुरेखा होटल और होटल हिल व्यू के पास के फुटेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह घटना स्थल के आसपास सक्रिय था।

हत्या से सीधा कनेक्शन और कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जमानत याचिका खारिज करते हुए विशेष अदालत ने टिप्पणी की कि वर्तमान में ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो मनसुख हिरन की हत्या से शेलार का सीधा संबंध साबित करते हैं। अदालत ने माना कि हत्या जैसी जघन्य साजिश में शेलार की सक्रिय भूमिका के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद उसे जमानत देना उचित नहीं होगा। इस फैसले के साथ ही शेलार की जेल से बाहर आने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

बचाव पक्ष की दलील

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि शेलार को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनकी दलील थी कि विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी से शेलार का कोई लेना-देना नहीं था। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज में शेलार की मौजूदगी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और केवल सह-आरोपियों से मिलना किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का पुख्ता प्रमाण नहीं माना जा सकता।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के विशेष अधिवक्ता सुनील गोंसाल्वेस ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अदालत के सामने यह बात रखी कि रिकॉर्ड में शेलार के खिलाफ केवल प्रथम दृष्टया (Prima Facie) सबूत ही नहीं, बल्कि कई ठोस और मजबूत डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं। एनआईए के अनुसार, शेलार इस पूरी साजिश की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है और उसकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने अपने आदेश में कॉल रिकॉर्ड्स का विशेष रूप से उल्लेख किया। जांच में पाया गया कि पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा और सचिन वझे जैसे मुख्य आरोपियों ने अलग-अलग सेल फोन के जरिए शेलार से संपर्क किया था। इसके अलावा, शेलार ने भी घटना के आसपास के समय में कई अन्य सह-आरोपियों को कॉल किए थे। इन तकनीकी साक्ष्यों ने शेलार के साजिश में शामिल होने के दावों को बल दिया है।

3 किलो हेरोइन के साथ पकड़ी गई विदेशी महिला बरी

जांच अधिकारियों पर गिरेगी गाज

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस (NDPS) अदालत ने 34 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी महिला को करीब तीन किलोग्राम हेरोइन की तस्करी के आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में न केवल महिला को दोषमुक्त किया, बल्कि जांच अधिकारियों की ₹गंभीर प्रक्रियागत लापरवाही और कर्तव्य में चूक₹ पर सख्त नाराजगी जताई है। विशेष न्यायाधीश यू सी देशमुख ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

'कठोर सजा वाले कानून में प्रक्रिया का पालन अनिवार्य'

विशेष अदालत ने 9 फरवरी को दिए अपने फैसले में कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब सजा का प्रावधान इतना कठोर है, तो जांच एजेंसी से कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना अपेक्षित है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा (2.96 किलोग्राम) और प्रकृति अपराध की गंभीरता को दर्शाती है, लेकिन एनसीबी अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न करने के कारण एक गंभीर मामले की आरोपी ₹सजा से बच गई₹। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

जांच में मिलीं गंभीर खामियां: सीसीटीवी फुटेज से लेकर गवाहों तक की लापरवाही

अदालत ने जांच टीम की कई बड़ी चूकों को उजागर किया। अभियोजन के अनुसार, हेयरड्रेसर प्रॉमिस खालिशवायो को फरवरी 2021 में हवाई अड्डे पर रोका गया था और उसके ट्रॉली बैग से हेरोइन मिलने का दावा किया गया था। हालांकि, अदालत ने पाया कि महिला की तलाशी एक ऐसे सहायक ने ली जिसे कानूनन इसका अधिकार नहीं था। साथ ही, जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एक महीने बाद आवेदन किया, तब तक डेटा मिट चुका था। इसके अलावा, एनसीबी मुकदमे के दौरान किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं कर सका, जबकि वे हवाई अड्डे के ही सुरक्षा गार्ड थे।

महिला अधिकारी की अनुपस्थिति को बताया कर्तव्य की अवहेलना

अदालत ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि एनसीबी के पास आरोपी के आगमन की जानकारी 12-14 घंटे पहले से थी, फिर भी टीम में कोई महिला अधिकारी शामिल नहीं थी। इसे अदालत ने ₹लापरवाही, उपेक्षा और कर्तव्य की पूर्ण अवहेलना₹ करार दिया। इन सभी प्रक्रियागत खामियों और साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए, अदालत ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को बरी करने का आदेश दिया और मुख्यालय को जांच टीम के सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

खेती-किसानी में अब 'एआई' की एंट्री

मुंबई में आयोजित होगी एआई कृषि विश्व परिषद

मुंबई। महाराष्ट्र के किसानों को खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वैश्विक तकनीक की नवीनतम जानकारी से लैस करने के लिए मुंबई में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की गई है। राज्य में कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'एआई कृषि विश्व परिषद' और 'इन्वेस्टर समिट' का आयोजन किया जा रहा है।

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह दो दिवसीय बहुप्रतीक्षित सम्मेलन 22 और 23 फरवरी को मुंबई के अत्याधुनिक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस हाई-प्रोफाइल इवेंट में देश और दुनिया भर से कृषि तकनीक से जुड़े कई अहम लोग शिरकत करेंगे।

'महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एआई पॉलिसी 2025-2029' के तहत पहल

यह विशाल परिषद राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एआई पॉलिसी 2025-2029' के विजन के तहत आयोजित की जा रही है। इस समिट में कृषि क्षेत्र के दिग्गज विशेषज्ञ, एग्री-टेक से जुड़े नए स्टार्टअप्स, बड़े निवेशक (इन्वेस्टर्स) और प्रमुख वित्तीय संस्थान (फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस) एक मंच पर आकर कृषि में निवेश और तकनीक पर मंथन करेंगे।

विश्व बैंक, WEF और ADB जैसे वैश्विक संगठनों का सहयोग

इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर सफल बनाने के लिए दुनिया के कई बड़े संगठन एक साथ आए हैं। इस परिषद का आयोजन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD), विश्व बैंक समूह (World Bank Group) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। आयोजन में वैश्विक वित्तीय और विकास संगठनों के अलावा, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले कई प्रमुख शोध संस्थान भी ग्लोबल और नेशनल पार्टनर्स के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे।

समारोहों में इस्तेमाल होने वाले घोड़े को मिली 'आज़ादी'

मुंबई कोर्ट ने क्रूरता के आरोप में जब्त घोड़े को मालिक को देने से रोका!

अब पशु कल्याण केंद्र में ही रहेगा घोड़ा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई की एक अदालत ने पशु क्रूरता के आरोप में जब्त किए गए एक घोड़े को उसके मालिक को सौंपने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की आजीविका कमाने के दावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पशु का कल्याण और उसकी सुरक्षा है। बता दें कि इस घोड़े का इस्तेमाल मुख्य रूप से पारंपरिक और वैवाहिक समारोहों में किया जाता था।

मझगांव अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबुद्दीन एस. शेख ने इस महीने की शुरुआत में मामले की सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया। उन्होंने घोड़े को उसके मालिक के सुपुर्द करने के बजाय, उसे पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक सुरक्षित केंद्र में रखने के मजिस्ट्रेट के पुराने निर्णय को ही सही माना और उसे बरकरार रखा है।

पेटा की शिकायत पर हुई थी जब्ती की कार्रवाई

यह मामला पिछले साल का है, जब दक्षिण मुंबई में पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत इस घोड़े को जब्त किया था। पुलिस की यह कार्रवाई जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा (पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स) द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी (FIR) के आधार पर की गई थी। इसके बाद मालिक ने घोड़े की वापसी के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की।

घोड़े के मालिक जगन्नाथ कुंजुप्रसाद राजभर का मुख्य व्यवसाय शादियों और पारंपरिक समारोहों में बग्गी के लिए घोड़े किराए पर देना है। राजभर ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया कि उनके पास सभी जरूरी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और उन्होंने जानवर के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल मई में एक शादी के दौरान किसी ने घोड़े की तस्वीर खींचकर यह पूरी तरह से झूठी एफआईआर दर्ज करा दी थी।

बिना लाइसेंस कारोबार करने पर मजिस्ट्रेट की सख्त टिप्पणी

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान जुलाई में मजिस्ट्रेट अदालत ने राजभर की याचिका को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा था कि राजभर शहर में यह कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई वैध लाइसेंस पेश नहीं किया। इसके बाद अदालत ने दो लाख रुपये के बांड पर घोड़े की अंतरिम हिरासत पेटा को सौंप दी थी, साथ ही यह शर्त भी रखी थी कि अदालत के निर्देश पर संगठन को घोड़ा वापस करना होगा। मजिस्ट्रेट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर राजभर ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। हालांकि, पेटा और मुंबई पुलिस ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि संपत्ति (इस मामले में घोड़ा) वापसी के आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं है। सत्र न्यायाधीश ने हस्तक्षेपकर्ता (पेटा) और पुलिस की इन दलीलों को दमदार और उचित मानते हुए राजभर की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।

पवार परिवार में 'मिलन' के संकेत

सुप्रिया सुले ने की पहल, सुनेत्रा पवार के अगले कदम पर टिकी निगाहें

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के संभावित विलय की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों गुटों के एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताते हुए कहा है कि यह भावना उनके मन में पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बड़े नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी पसंद नहीं करती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ सुप्रिया सुले के इस बयान को दोनों गुटों के बीच बातचीत के दरवाजे खुले रखने और भविष्य में साथ आने के एक अहम संकेत के रूप में देख रहे हैं।

रोहित पवार के लिए सुरक्षा और विमान हादसे की जांच की मांग

राजनीतिक विलय के संकेतों के अलावा, सांसद सुप्रिया सुले ने विधायक रोहित पवार की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार से रोहित पवार को तुरंत सरकारी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करते हुए कहा कि वे लगातार जनता से जुड़े अहम मुद्दे उठा रहे हैं, जिससे कई लोगों को उनकी सुरक्षा की फिक्र है। इसके साथ ही, सुप्रिया सुले ने हाल ही में हुए विमान दुर्घटना मामले का मुद्दा भी उठाया।

पश्चिम रेलवे

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC)
पता: पार्सल डिपो, अलीभाई प्रेमजी रोड, ग्रांट रोड (पूर्व), मुंबई – 400007
वेबसाइट: https://www.rrc-wr.com

पश्चिम रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती हेतु सांकेतिक अधिसूचना

अधिसूचना संख्या: RRC/WR/04/2025 (अप्रेंटिस) दिनांक: 18/02/2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ	21/02/2026 प्रातः 11:00 बजे
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	23/03/2026 सायं 17:00 बजे

1) **पश्चिम रेलवे इच्छुक उम्मीदवारों से वर्ष 2025-2026** के लिए विभिन्न मंडलों, कार्यशालाओं एवं इकाइयों में अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु कुल **5349** पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
2) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही **23/03/2026 को सायं 17:00 बजे** तक जमा करना है।
3) अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार RRC-WR की आधिकारिक वेबसाइट **https://www.rrc-wr.com** पर लॉगिन करें।

1140

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि फ्लैट नंबर A/1403, जिसका कार्पेट क्षेत्र लगभग 71.8 वर्ग मीटर है, 14वीं मंजिल पर स्थित है। इसके साथ पोडियम के दूसरे स्तर पर कार पार्किंग स्थान नंबर 39 तथा दूसरे फ्लोर स्तर पर खुला कार पार्किंग स्थान नंबर 11 भी शामिल है। यह संपत्ति "SHIV SHRUSHTI" नामक इमारत में स्थित है, जो महावीर नगर शिव सृष्टि को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के अंतर्गत, प्लॉट नंबर PH-1, RDP 12 एवं 13, CTS नंबर 1C-1/1, लिंक रोड, महावीर नगर, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई – 400067 में स्थित है।

उक्त फ्लैट के 50% अविभाजित अधिकार तथा 10 पूर्ण रूप से चुकता योग्य शेयर (प्रत्येक 50/- मूल्य के), जिनके विशिष्ट क्रमांक **441 से 450** (दोनों सहित) हैं और जो शेयर प्रमाणपत्र नंबर **45** में दर्ज हैं, **स्वर्गीय श्री पंकज वी. शाह** (जिनका निधन दिनांक 13/06/2015 को हुआ) के नाम से उनके पुत्रों **श्री अंकित पंकज शाह एवं श्री वत्सल पंकज शाह** के नाम हस्तांतरित किए गए हैं।

उपरोक्त फ्लैट एवं शेयरों में शेष 50% अविभाजित अधिकार पहले से ही **श्रीमती हीना पंकजकुमार शाह** के नाम पर दर्ज हैं।

दिनांक 22 जनवरी, 2026 के विक्रय अनुबंध (दस्तावेज क्रमांक MBI18-1053-2026) के अनुसार, **श्रीमती हीना पंकजकुमार शाह, श्री अंकित पंकज शाह एवं श्री वत्सल पंकज शाह** ने उक्त फ्लैट एवं शेयरों को **श्री भगवत जी. जायसवाल एवं श्रीमती ऋतु भगवत जायसवाल** को विक्रय कर दिया है।

यदि किसी व्यक्ति का उक्त संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार, विक्रय, बंधक, प्रभार, ट्रस्ट, धारणाधिकार (लीन), कब्जा, उपहार, भरण-पोषण, पट्टा, कुर्की या किसी अन्य प्रकार से कोई दावा, अधिकार, स्वामित्व या हित हो, तो वह इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपना दावा लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को उनके पते — दुकान नं. 14, अक्रुति अपार्टमेंट, मथुरादास रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई – 400 067 तथा संबंधित सोसायटी को सूचित करें।

निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावे को त्यागित एवं/या परित्यक्त माना जाएगा।

हस्ताक्षर/-
(श्रीमती रशीदा वाई. लक्ष्मीधर)
अधिवक्ता

दिनांक: 20/02/2026

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्रमांकः उप.मुख्य अभियंता / M&E / 4669/W.S. दिनांक 18.02.2026

ई-निविदा सूचना

बृहन्मुंबई के मनपा आयुक्त पात्र बोलीदाताओं से "आइटम रेट बेसिस" पर निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन ई-निविदाएँ आमंत्रित करते हैं। बोली प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि व समय का विवरण MCGM की वेबसाइट के "Tenders" अनुभाग में उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना में दिया गया है।

विभाग : मुख्य अभियंता (M&E)	अनुभागः उप मुख्य अभियंता (M&E) W.S
निविदा क्रमांकः	2026_MCGM_1279534_1
कार्य का विषय	ठाकुर विलेज फायर स्टेशन, कांदिवली (पूर्व), आर/एस वार्ड में पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ज़ोन इंडिकेटर सिस्टम तथा संबंधित कार्यों का SITC (Supply, Installation, Testing & Commissioning) कार्य।
बोली प्रारंभ तिथि बोली समाप्ति तिथि	20.02.2026, समयः प्रातः 11:00 बजे 26.02.2026, समयः सायं 4:00 बजे
संपर्क a) नामः b) दूरभाष c) ई-मेलः	कार्यकारी अभियंता (M&E) W.S.-I श्री जे. डी. शिरसाठ 022-29677905 eews01.me@mcgm.gov.in

इच्छुक निविदाकार अधिक जानकारी हेतु नगर निगम की वेबसाइट http://portal.mcgm.gov.in/ https://mahatenders.gov.in पर देखें।
निविदा दस्तावेज डाक/कूरियर द्वारा जारी या स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

हस्ता/-
कार्यकारी अभियंता (M&E) W.S.-I

पीआरओ/3028 / विज्ञा./2025-26

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

आरे कॉलोनी में बेस्ट बस और कार की टक्कर, चालक घायल

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई के आरे कॉलोनी इलाके में गुरुवार सुबह 'बेस्ट' (BEST) की एक मिडी बस ने सामने से आ रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार चालक घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए जोगेश्वरी स्थित बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुँचा है।

ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हुई बस

हादसे का शिकार हुई बस (मार्ग क्रमांक ए-451) मागाठणे डिपो की 'डागा ग्रुप' द्वारा संचालित भाड़े की बस (Leased Bus) थी। जानकारी के अनुसार, बस गोरेगाव स्टेशन (पूर्व) से आदर्श नगर की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित होकर बस पहले कार से टकराई और फिर एक पेड़ से जा टकराई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। पिछले कुछ दिनों में बेस्ट के बेड़े में शामिल निजी ऑपरेटरों (भाड़े) की बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है।

6386
11/02/2026

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
प्रत्यर्थी को आवेदन की सूचना नोटिस
(अधिनियम क्रमांक ५ सन १९०८ आदेश इकतालिस, नियम १४) आवेदन क्रमांक ARBR 20/2025
Jaysawal Neco Industries Limited
विरूद्ध Krupay Industries
Application for request to appoint an arbitrator under section 11 (5) and (6) of the arbitration and conciliation act 1996 R/W scheme for appointment arbitrator
प्रति, अनावेदक - Krupay Industries.
Corporate Office No 115, Cama Industrial Estate Lower Parel Mumbai - 400013
कृपया सूचित करें कि ऊपर वर्णित आवेदन Jaysawal Neco Industries Limited के द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीकृत की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा आवेदन की सुनवाई का दिनांक 18.03.2026 नियत की गई है। आपत्तियां/प्रति आपत्तियां यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से नियत तिथि के पूर्व फाइल की जानी चाहिए।
आपको आवेदन की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार रहना चाहिए किन्तु यदि न्यायालय के काम काज के कारण आवेदन उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यदि अपनी ओर से आप स्वयं आपका वकील या इस के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिये विधिवतब प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तो आवेदन आपकी अनुपस्थिति में सुनी जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़,बिलासपुर की मुहर से दिया गया।
अस्सिटेंट रजिस्ट्रार,
सिविल शाखा

संपादकीय

मुफ्त की रेवड़ियां

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कल्याणकारी योजनाओं की अहम भूमिका रही है। गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों तक सहायता पहुंचाना राज्य का नैतिक दायित्व है। लेकिन जब यह सहायता नीति और चुनावी रणनीति का फर्क मिटा दे, तब सवाल उठना स्वाभाविक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति पर जो टिप्पणी की है, वह इसी बुनियादी चिंता को सामने लाती है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारें सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, गैस और बिजली देती रहेंगी, तो काम करने की प्रवृत्ति कमजोर होगी। समाज की रीढ़ मेहनत और उत्पादन पर टिकी होती है। अगर आजीविका का विकल्प श्रम के बजाय अनुदान बन जाए, तो आत्मनिर्भरता का सपना खोखला हो सकता है। अदालत की यह टिप्पणी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक चेतावनी भी है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने तीन अहम प्रश्न उठाए कि क्या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जहां लोग कमाने के बजाय पाने पर निर्भर रहें? चुनाव के समय ही उदार घोषणाएं क्यों होती हैं? और क्या बिना पात्रता तय किए मुफ्त सुविधाएं देना तुष्टीकरण की नीति नहीं है? ये सवाल राजनीतिक दलों और नीति-निर्माताओं दोनों के लिए आत्ममंथन का अवसर हैं। यह मामला तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका से जुड़ा है, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना मुफ्त बिजली देने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त देती है। सिद्धांततः यह राहत गरीब परिवारों के लिए सहारा हो सकती है, लेकिन व्यवहार में इसका लाभ मध्यम और संपन्न वर्ग को भी समान रूप से मिलता है। यही वह बिंदु है, जहां नीति की संवेदनशीलता और विवेक पर प्रश्न उठता है। भारत के कई राज्य पहले से ही राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं। ऐसे में व्यापक मुफ्त योजनाएं वित्तीय अनुशासन को कमजोर कर सकती हैं। विकास कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और रोजगार सृजन के लिए धन की जरूरत होती है। यदि बजट का बड़ा हिस्सा मुफ्त सुविधाओं में खर्च होगा, तो दीर्घकालिक निवेश कैसे होगा? अदालत ने सही कहा कि संतुलन जरूरी है। न तो कल्याण को छोड़ा जा सकता है और न ही विकास को। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अर्थ यह नहीं कि हर सुविधा बिना शर्त दी जाए। इसका आशय यह है कि जो वास्तव में असमर्थ हैं, उन्हें लक्षित सहायता मिले। बिजली का बिल न चुका पाने वालों को राहत देना उचित है, लेकिन जो भुगतान करने में सक्षम हैं, उन्हें भी मुफ्त सुविधा देना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि संसाधनों की बर्बादी भी है। इससे सामाजिक न्याय की भावना कमजोर होती है। मुफ्त योजनाओं का एक और पहलू राजनीतिक है। चुनाव से पहले इनकी घोषणा अक्सर मतदाताओं को लुभाने का साधन बन जाती है। अल्पकालिक लोकप्रियता के लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को दांव पर लगाना लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। नीति निर्माण का उद्देश्य वोट नहीं, बल्कि भविष्य होना चाहिए। अदालत की टिप्पणी को केवल न्यायिक फटकार समझना भूल होगी। यह एक व्यापक चेतावनी है कि भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और कौशल विकास ये तीन स्तंभ मजबूत होंगे, तभी कल्याण योजनाएं सार्थक होंगी। मुफ्त की संस्कृति श्रम की संस्कृति का विकल्प नहीं बन सकती। अंततः सवाल यही है कि क्या हम मेहनत से कमाने वाला समाज चाहते हैं या अनुदान पर निर्भर समाज?

शख्सियत

अजीमुल्ला खां

क्रांति का रणनीतिकार

1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में झांकें, तो हमें तलवार चलाने वाले कई शूरवीरों के नाम मिलते हैं, लेकिन उस क्रांति की वैचारिक नींव रखने वाले और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष मजबूत करने वाले नायकों में अजीमुल्ला खाँ का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।

वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक प्रखर कूटनीतिज्ञ, बहुभाषी विद्वान और आधुनिक सोच रखने वाले दूरदर्शी नेता थे। अजीमुल्ला खां का जन्म 20 फरवरी, 1830 को एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने भीषण अकाल और गरीबी का सामना किया। कहा जाता है कि कानपुर की सड़कों पर भूखे रहने के बावजूद उनमें सीखने की अदम्य इच्छा थी। उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं पर असाधारण पकड़ बनाई। उनकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता ही थी कि कानपुर के पेशवा नाना साहेब ने उन्हें अपना सचिव और राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया। लंदन की यात्रा और अपमान का प्रतिशोध अजीमुल्ला खाँ के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब नाना साहेब की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी।

इस मामले की पैरवी के लिए अजीमुल्ला खाँ लंदन गए। लंदन की अदालतों और उच्च समाज में अपनी धाराप्रवाह अंग्रेजी और शिष्टाचार से उन्होंने सबको प्रभावित किया, लेकिन अंततः 'ईस्ट इंडिया कंपनी' ने उनकी दलीलों को ठुकरा दिया। इस अपमान ने अजीमुल्ला के भीतर की देशभक्ति को एक नई दिशा दी। उन्हें समझ आ गया कि अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है; उन्हें केवल शक्ति के बल पर ही हटाया जा सकता है। लंदन से लौटते समय वे तुर्की (कॉन्स्टेंटिनोपल) और रूस भी गए, जहाँ उन्होंने क्रीमिया युद्ध का अध्ययन किया और यह समझा कि ब्रिटिश सेना अपराजेय नहीं है। भारत लौटकर अजीमुल्ला खाँ ने नाना साहेब के साथ मिलकर पूरे देश में विद्रोह की गुप्त योजना बनाई। उन्होंने महसूस किया कि बिखरी हुई रियासतें अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकतीं, इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया। क्रांति के प्रचार के लिए उन्होंने 'चपाती और कमल' के प्रतीक का उपयोग किया, जो एक गाँव से दूसरे गाँव तक गुप्त संदेश पहुँचाने का एक नायाब तरीका था। वे केवल एक योजनाकार ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने 'पयाम-ए-आज़ादी' नामक अखबार भी निकाला, जिसके माध्यम से जनता में राष्ट्रवाद की ज्वाला फूंकी। उन्होंने नारा दिया था कि ₹हम इसके मालिक हैं, हिंदुस्तान हमारा है,₹ जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। 1857 का विद्रोह जब अपने चरम पर था, तब अजीमुल्ला खाँ युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीतिक मोर्चों तक सक्रिय रहे। जब क्रांति को अंग्रेजों ने बेरहमी से दबाना शुरू किया, तो वे नाना साहेब के साथ नेपाल की तराई के जंगलों में चले गए। भीषण परिस्थितियों, बीमारी और संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। 1859 में इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने मातृभूमि की गोद में अंतिम सांस ली। अजीमुल्ला खां का जीवन हमें सिखाता है कि साधनहीनता कभी सफलता के आड़े नहीं आती। एक गरीब बच्चा अपनी मेहनत से सात समुंदर पार जाकर अंग्रेजों की आँखों में आँखें डालकर बात कर सकता है।

परीक्षा से बड़ी है जिंदगी : अंक केवल संकेत हैं, मूल्य नहीं

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

हिंदी साहित्यकार, लेखक और शिक्षाविद् हैं। बड़वानी (मप्र) में निवास

परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभा की जाँच है, न कि घड़ी की सुइयों की पूजा। यदि चाहा जाता तो कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सकता था—जैसा अन्य परिस्थितियों में निकाला भी गया। पर यहाँ नियमों की दीवार ऊँची कर दी गई और मानवीय विवेक को बाहर छोड़ दिया गया। परिणाम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा।

कभी-कभी बस एक छोटा-सा क्षण पूरी व्यवस्था की आत्मा को बेनकाब कर देता है। घड़ी ने दस मिनट का फासला तय किया—और एक बच्ची परीक्षा कक्ष के बाहर रह गई। वही दस मिनट उसके जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन गए। नियम अपनी जगह अडिग खड़े रहे, पर जीवन चुपचाप फिसल गया। दूसरी ओर, एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र कम पड़े तो उसी तंत्र ने नियमों को मोड़कर दो पालियों में परीक्षा करा दी। यही विरोधाभास हमारे समय की नंगी सच्चाई है—जहाँ सुविधा हो वहाँ नियम लचीले, और जहाँ करुणा चाहिए वहाँ वे पत्थर बनकर गिरते हैं। दस मिनट की देरी पर दरवाज़ा बंद कर देना नियम की कठोरता नहीं, संवेदना की विफलता है।

परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभा की जाँच है, न कि घड़ी की सुइयों की पूजा। यदि चाहा जाता तो कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सकता था—जैसा अन्य परिस्थितियों में निकाला भी गया। पर यहाँ नियमों की दीवार ऊँची कर दी गई और मानवीय विवेक को बाहर छोड़ दिया गया। परिणाम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा, वह एक असहनीय त्रासदी में बदल गया। प्रश्न नियमों के अस्तित्व का नहीं, उनमें जीवित मनुष्यता की उपस्थिति का है। क्या व्यवस्था इतनी यांत्रिक हो चुकी है कि उसे परिस्थितियों की धड़कन सुनाई ही नहीं देती? इसी क्रम में दूसरी घटना ने तंत्र का दूसरा चेहरा भी दिखाया। जब प्रश्नपत्र कम पड़ गए और व्यवस्था की अपनी भूल उजागर हुई, तो तुरंत समाधान तलाश लिया गया। दो पालियाँ बनीं, प्रतियाँ तैयार हुईं, समय-सारिणी बदली—और परीक्षा पूरी करा दी गई। यहाँ नियमों को मोड़ना संभव था, क्योंकि आवश्यकता थी। यही

विरोधाभास सबसे चुभता है—जहाँ सिस्टम की असुविधा हो, वहाँ लचीलापन; जहाँ छात्र की मजबूरी हो, वहाँ कठोरता क्यों?

क्या नियम केवल नीचे की ओर सख्त और ऊपर की ओर नरम होते हैं? क्या करुणा का पैमाना भी पद और अधिकार देखकर बदल जाता है? पर इस पूरी पीड़ा का एक और पक्ष भी है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती। अंक केवल भविष्य की दिशा तय करते हैं, अस्तित्व की कीमत नहीं। देर हो जाए तो अगला अवसर मिलता है, अगला प्रयास संभव है, अगला वर्ष भी आता है। पर यदि जीवन का पन्ना ही फाड़ दिया जाए, तो उसे कोई परिणाम फिर नहीं जोड़ सकता। क्षणिक आवेग में उठाया गया चरम कदम समस्या का समाधान नहीं, परिवार के लिए आजीवन घाव बन जाता है। हमें यह समझना और समझाना होगा कि असफलता अंत नहीं, अनुभव है; ठोकर हार नहीं, आगे बढ़ने की तैयारी है। हमारे समाज ने परीक्षा को उपलब्धि से आगे बढ़ाकर प्रतिष्ठा और पहचान का पैमाना बना दिया है। अंक अब केवल परिणाम नहीं रहे, वे मानो सम्मान का प्रमाणपत्र बन गए हैं। माता-पिता की आकांक्षाएँ, रिश्तेदारों की तुलना और सोशल मीडिया की चकाचौंध—ये सब मिलकर एक कोमल मन पर ऐसा दबाव रचते हैं, जो दिखाई नहीं देता पर भीतर गहराई तक चुभता है।

ऐसे माहौल में दस मिनट की देरी महज़ समय का अंतर नहीं रह जाती; वह मानो सपनों के ढह जाने का प्रतीक बन जाती है। यहीं परिवार और विद्यालय की असली भूमिका शुरू होती है। बच्चों को सिखाना होगा कि जीवन की कीमत किसी परिणाम से कहीं अधिक है। परीक्षा एक अवसर है, अस्तित्व का अंतिम सत्य नहीं। प्रशासन की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं, पर उनका उद्देश्य मनुष्यों की रक्षा करना है, उन्हें तोड़ना नहीं। यदि कोई नियम ऐसी स्थिति पैदा करे जहाँ जीवन ही संकट में पड़ जाए, तो उसके स्वरूप पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। हर परीक्षा केंद्र पर मानवीय विवेक की एक खिड़की खुली रहनी चाहिए—ऐसी व्यवस्था, जहाँ आपात स्थिति में समाधान खोजा जा सके। जब तकनीकी त्रुटियों पर तत्काल विकल्प संभव हैं, तो कुछ मिनट की देरी पर संवेदना असंभव क्यों प्रतीत होती है? प्रशासनिक दक्षता के साथ संवेदनशीलता भी अनिवार्य प्रशिक्षण का हिस्सा बननी चाहिए। छात्रों के लिए यह घटना एक चेतावनी भी है और एक सीख भी। समयपालन कोई औपचारिक नियम नहीं।

हमारी गीता

दुर्योधन का अस्थिर विश्वास

स्वामिनी निष्कलानंदा

चिन्मय मिशन कल्याण

भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में दुर्योधन का आचरण उसके मन की अस्थिरता और छिपे हुए भय को प्रकट करता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने कौरव सेना की प्रशंसा करता है और यह कहकर आत्मविश्वास दिखाता है कि उनके सेनापति भीष्म पितामह जैसे अपराजेय योद्धा हैं। परंतु उसी क्षण वह समस्त सैनिकों को आदेश देता है कि वे भीष्म की रक्षा करें। यह कथन अपने आप में विरोधाभासी है। जो समूची सेना के रक्षक हैं, उनकी ही रक्षा का आग्रह क्यों? यहां दुर्योधन के अंतर्मन की शंका प्रकट होती है। उसे भीष्म की शक्ति पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों पर संशय है। संभवतः उसे भय था कि भीष्म हृदय से पांडवों के प्रति कोमल हैं। इसीलिए वह

सैनिकों को भीष्म के चारों ओर सजग रहने को कहता है। यह व्यवहार एक सच्चे आत्मविश्वासी नेतृत्व का नहीं, बल्कि आशंकित मन का प्रतीक है। दूर-दूर से आए राजाओं और योद्धाओं को एक सूत्र में बांधे रखना भी दुर्योधन के लिए चुनौती था। भीष्म के प्रति सबका पूज्यभाव ही कौरव सेना का मनोबल था। यदि भीष्म न होते, तो सेना का धैर्य डगमगा सकता था। इसलिए दुर्योधन की चिंता स्वाभाविक भी थी, पर उसका प्रदर्शन हास्यास्पद प्रतीत होता है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन की दयनीय मानसिक स्थिति को समझ लिया। उन्होंने शंखनाद कर युद्ध का आरंभ किया, मानो सबको मानसिक उलझनों से बाहर निकालना चाहते हों। सिंहनाद के समान गूंजता वह शंख केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, बल्कि भ्रम और भय पर कर्तव्य की विजय का उद्घोष भी था।

जीवन ऊर्जा

जन्म

जेम्स गॉर्डन ब्राउन : जन्म -20 फरवरी, 1830

21वीं सदी में ज्ञान ही असली शक्ति है

जेम्स गॉर्डन ब्राउन का जन्म 20 फरवरी 1951 को ब्रिटेन में हुआ। वे ब्रिटेन के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 2007 से 2010 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे लेबर पार्टी के नेता थे और उससे पहले लंबे समय तक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर रहे। गॉर्डन ब्राउन अभी जीवित हैं और वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं।

अर्थव्यवस्था केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का साधन है। स्थिरता ही वह नींव है जिस पर समृद्धि का निर्माण होता है। वैश्वीकरण को हमें अपने पक्ष में मोड़ना होगा, न कि उससे डरकर भागना होगा। बाजार के पास दिल नहीं होता, इसलिए सरकार को उसमें नैतिकता लानी पड़ती है। निवेश केवल खर्च नहीं है, यह भविष्य के प्रति हमारा विश्वास है। वित्तीय संकट हमें सिखाते हैं कि जिम्मेदारी के बिना आजादी खतरनाक है। कर चोरी केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज के साथ विश्वासघात है। शिक्षा ही वह पासपोर्ट है जो गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। हर बच्चे में प्रतिभा होती है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। 21वीं सदी में ज्ञान ही असली शक्ति है। स्कूल केवल इमारतें नहीं, बल्कि भविष्य की प्रयोगशालाएं हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम शिक्षा में निवेश नहीं करते, तो हम अपने भविष्य के साथ समझौता कर रहे हैं। गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह इंसानों द्वारा बनाई गई व्यवस्था का परिणाम है। हमें

एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ जन्म का स्थान भविष्य तय न करे। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा युद्ध है जिसे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। वैश्विक समस्याओं के लिए राष्ट्रीय समाधान पर्याप्त नहीं हैं। मदद करना दान नहीं, बल्कि न्याय का एक हिस्सा है। अफ्रीका के साथ अन्याय पूरी मानवता के माथे पर कलंक है। शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि न्याय की उपस्थिति है। नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि सेवा करना है। राजनीति में चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवर्तन कठिन होता है, लेकिन प्रगति के लिए अनिवार्य है। हमें वह करने की हिम्मत रखनी चाहिए जो सही है, न कि वह जो लोकप्रिय है। लोकतंत्र केवल वोट देने तक सीमित नहीं, यह सक्रिय भागीदारी का नाम है। शक्ति का असली परीक्षण यह है कि आप उसका उपयोग किसके लिए करते हैं। हम एक समाज हैं, न कि केवल व्यक्तियों का समूह। समानता का अर्थ यह नहीं कि सबको एक जैसा बनाया जाए।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

विश्वास, विवेक और साधना का सही उद्देश्य

मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की जड़ में दो ही मूल तत्व होते हैं—विश्वास और विवेक। विश्वास से भक्ति का जन्म होता है और विवेक से ज्ञान का। जब ये दोनों संतुलित रूप में व्यक्ति के भीतर विकसित होते हैं, तभी उसका जीवन सार्थक दिशा में आगे बढ़ता है। परंतु यदि श्रद्धा का आधार केवल स्वार्थ या मोह हो, तो साधना का वास्तविक उद्देश्य खो जाता है मनुष्य के अंतःकरण में अक्सर मोह, अहंकार और इच्छाओं का अंधकार छाया रहता है। यही अंधकार एक गांठ की तरह उसके भीतर जम जाता है। इस गांठ को खोलना ही आध्यात्मिक साधना का मुख्य लक्ष्य है। इसे खोलने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना पड़ता है। जैसे दीपक के लिए घृत चाहिए, घृत के लिए दूध और दूध के लिए गाय, वैसे ही ज्ञान के लिए श्रद्धा, सत्कर्म और साधना की आवश्यकता होती है। श्रद्धा रूपी गाय

को सत्कर्म का चारा खिलाना पड़ता है। यदि जप, तप, यम और नियम में श्रद्धा का अभाव हो, तो वे क्रियाएं केवल बाहरी औपचारिकता बनकर रह जाती हैं और उनका अपेक्षित फल नहीं मिलता। श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है—सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा वही है, जिसमें निस्वार्थ भाव हो और जिसका उद्देश्य आत्मोन्नति या परम सत्य की प्राप्ति हो। इसके विपरीत, यदि साधना केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाए, तो वह राजसिक श्रद्धा बन जाती है। और यदि किसी के अहित या विनाश की भावना से जप-तप किया जाए, तो वह तामसिक श्रद्धा कहलाती है। इसलिए केवल साधना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पीछे की भावना और उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। रावण का जीवन इसका सशक्त उदाहरण है। वह महान तपस्वी था, जिसने कठोर साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। परंतु जब वरदान मांगने का समय आया, तो उसने भक्ति और ज्ञान के बजाय अपनी सुरक्षा और अहंकार को चुना। उसने मनुष्य के हाथों मृत्यु की कामना कर ली और यही उसकी विनाश का कारण बना। यदि वह विश्वास से भक्ति और विवेक से ज्ञान मांगता, तो उसका जीवन धन्य हो सकता था। उसकी साधना महान थी, पर उसका उद्देश्य गलत था। महाभारत में गांधारी का उदाहरण भी यही शिक्षा देता है। उसने पति के प्रति समर्पण दिखाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह त्याग महान था, परंतु विवेकपूर्ण नहीं था। यदि वह अपनी दृष्टि का उपयोग करके दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर ले जाती, तो शायद इतिहास बदल सकता था। बाद में जब उसने अपने तप से दुर्योधन को अजेय बनाने का प्रयास किया, तब भी विवेक का अभाव दिखाई दिया। परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन स्वयं अपनी कमजोरी का कारण बन गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि साधना का मूल्य केवल उसकी मात्रा या कठोरता से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य से तय होता है। जप, तप और पूजा केवल कर्म नहीं हैं; वे साधन हैं, जिनसे हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। जैसे धन से व्यक्ति पूजा की सामग्री भी खरीद सकता है और विष भी, वैसे ही साधना से भक्ति और ज्ञान भी मिल सकता है और विनाश का मार्ग भी खुल सकता है।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा

वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

अपने विचार

मुसलमान अपने धर्म के बल पर जीवित हैं और जीवित रहेंगे। भारत में शांति और सद्भाव केवल धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे के तहत ही संभव है। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सभी धर्म मानवता, सहिष्णुता, प्रेम और एकता का उपदेश देते हैं।

मौलाना अरशद मदनी
अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिंद

दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनके समाधान भारत के पास हैं। पश्चिमी देश कट्टरता फैलाते हैं. उनकी सोच है कि शक्तिशाली बनो, अपने लिए जियो और बाकी को छोड़ दो, जो रास्ते में आए उसे समाप्त कर दो। आज अमेरिका और चीन यही कर रहे हैं।

मोहन भागवत
सरसंघचालक,RSS

भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है.....सबसे बड़े टैग टैलेंट पूल का केंद्र है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है, और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है. इस समिट का भारत में होना, भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते समय आपसे सभी के प्रति निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है। आपसे संविधान का पालन करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, राज्य और केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही हैं। उच्च न्यायालय ने भी आंशिक रूप से कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया था।

नाना पटोले
नेता, कांग्रेस

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001

indiagroundreport@gmail.com

भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com **कार्यकारी संपादक :** अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

ठाणे मनपा में मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती

ठाणे। ठाणे महानगरपालिका (मनपा) ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर मेयर शर्मिला पिंपलोलकर, डिप्टी मेयर कृष्णा पाटिल और म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव ने मनपा स्थित स्वर्गीय नरेंद्र बल्लाल हॉल में शिवाजी महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद, सभी गणमान्य व्यक्तियों ने मासुंदा तालाब स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की आदमकद प्रतिमा पर भी फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस खास मौके पर मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने ठाणे के सभी निवासियों को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुख्य समारोह के अलावा, डिप्टी मेयर कृष्णा पाटिल ने कलवा नाका स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की आदमकद प्रतिमा पर भी अलग से फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिव जयंती के इस पावन अवसर पर मनपा के कई वरिष्ठ अधिकारी और जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इनमें एडिशनल कमिश्नर (2) प्रशांत रोडे, शिवसेना ग्रुप लीडर पवन कदम, डिप्टी कमिश्नर जी.जी. गोदापुरे, उमेश बिरारी, दीपक जिंजाड़, टीएमटी के जीएम भालचंद्र बेहरे, असिस्टेंट कमिश्नर ललिता जाधव और सोपान भाईक सहित मनपा के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे।

भिवंडी के निसर्गोपचार विशेषज्ञ स्वप्नील म्हात्रे 'आयुष महासम्मान 2025' से सम्मानित

भिवंडी। भिवंडी तालुका के खारबाव और डोंबिवली क्षेत्र के प्रसिद्ध निसर्गोपचार विशेषज्ञ स्वप्नील प्रभाकर म्हात्रे को नवी मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित 'आयुष महासम्मान पुरस्कार 2025' से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें उनके संस्थान 'श्री मेख आयुर्धाम' के माध्यम से आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों द्वारा सैकड़ों मरीजों का सफल इलाज करने के लिए दिया गया है। आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन और भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से संबद्ध संस्था के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अभिनेत्री श्रेया बुगाडे और विधायक श्वेता म्हाले ने उन्हें यह पुरस्कार सौंपा। इस खास अवसर पर डॉ. मंगला कोहली सहित देशभर के कई आयुष चिकित्सक और थेरपिस्ट मौजूद थे; स्वप्नील म्हात्रे की इस शानदार उपलब्धि को पूरे भिवंडी और डोंबिवली क्षेत्र के लिए बड़े गर्व का विषय माना जा रहा है।

अपने घर में मृत पाए गए फिल्म निर्माता एमएम बेग

मुंबई। दिग्गज फिल्म निर्माता एम एम बेग अपने घर में मृत पाए गए। वह 70 वर्ष के थे। उनके प्रबंधक हनीफ जावेरी ने यह जानकारी दी। लोकप्रिय बाल कलाकार बेबी गुड्डू के पिता बेग 'रजिया सुल्तान' जैसी फिल्मों से जुड़े रहे तथा 'छोटी बहू' का निर्देशन किया था। बेग ने अपने करियर की शुरुआत जे ओम प्रकाश, विमल कुमार और राकेश रोशन के सहायक के रूप में की। वह गोविंदा की 'आदमी खिलौना है', 'जैसी करनी वैसी भरनी', 'कर्ज चुकाना है' तथा अनिल कपूर अभिनीत 'काला बाजार' और 'किशन कन्हैया' जैसी फिल्मों से भी जुड़े रहे। निर्देशक के तौर पर उन्होंने दो फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें नसीरुद्दीन शाह अभिनीत 'मासूम गवाह' (1990) और शिल्पा शिरोडकर अभिनीत 'छोटी बहू' (1994) शामिल हैं। जावेरी ने कहा, ''बेग साहब के राकेश रोशन साहब से बहुत अच्छे संबंध थे। उन्हें उच्चारण, स्वर नियंत्रण और डायलॉग की अच्छी समझ थी, इसलिए वे ऋतिक रोशन की मदद करते थे।

रेलवे के 'स्पेशल 30' सफर बनाएंगे लल्लनटॉप

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने और त्योहारी सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे ने होली के अवसर पर 30 अतिरिक्त विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है। इन सेवाओं को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: पहला, लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) मुंबई से सुल्तानपुर और वाराणसी के बीच 8 नई वातानुकूलित (AC) विशेष ट्रेनें। दूसरा, एलटीटी मुंबई से रक्सौल, सहरसा और धनबाद के बीच पहले से चल रही 22 विशेष ट्रेन सेवाओं का होली तक विस्तार।

एलटीटी मुंबई - रक्सौल विशेष ट्रेन सेवाओं का विस्तार (8 सेवाएं)

मुंबई और रक्सौल के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन को अब होली के लिए विस्तारित कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 05558 (एलटीटी-रक्सौल) अब 12 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक हर गुरुवार को चलेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 05557 (रक्सौल-एलटीटी) 10 मार्च से 31 मार्च 2026 तक हर मंगलवार को संचालित होगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल रहेंगे।

एलटीटी मुंबई - सुल्तानपुर होली विशेष ट्रेन (4 सेवाएं)

सुल्तानपुर के लिए ट्रेन संख्या 04211 एलटीटी मुंबई से 27 फरवरी और 3 मार्च 2026 को दोपहर 14:35 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 23:00 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04212 सुल्तानपुर से 26 फरवरी और 2 मार्च 2026 को सुबह 04:00 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 12:20 बजे एलटीटी पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव ठाणे, कल्याण, भुसावल, इटारसी, झाँसी, कानपुर सेंट्रल और लखनऊ सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर होगा।

एलटीटी मुंबई - वाराणसी होली विशेष ट्रेन (4 सेवाएं)

वाराणसी जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन संख्या 04225 एलटीटी से 26 फरवरी और 2 मार्च 2026 को दोपहर 14:35 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 02:05 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04226 वाराणसी से 25 फरवरी और 1 मार्च को 01:35 बजे चलकर अगले दिन 12:20 बजे एलटीटी पहुंचेगी। सुल्तानपुर और वाराणसी जाने वाली इन दोनों विशेष ट्रेनों में 16 एसी 3-टियर इकोनॉमी कोच और 2 जेनरेटर वैन की सुविधा उपलब्ध होगी।

एलटीटी मुंबई - सहरसा विशेष ट्रेन सेवाओं का विस्तार (8 सेवाएं)

बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एलटीटी और सहरसा के बीच की ट्रेन सेवाओं को भी बढ़ाया गया है। ट्रेन संख्या 05586 (एलटीटी-सहरसा) अब 8 मार्च से 29 मार्च 2026 तक प्रत्येक रविवार को अपनी सेवाएं देगी। इसी प्रकार, वापसी के लिए ट्रेन संख्या 05585 (सहरसा-एलटीटी) को 6 मार्च से 27 मार्च 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार के लिए विस्तारित किया गया है। इसमें भी एसी, स्लीपर और सामान्य कोच की सुविधा मिलेगी।

एलटीटी मुंबई - धनबाद विशेष ट्रेन सेवाओं का विस्तार (6 सेवाएं)

त्योहार पर घर जाने वालों के लिए एलटीटी और धनबाद के बीच चलने वाली ट्रेनों का भी विस्तार किया गया है। ट्रेन संख्या 03380 (एलटीटी-धनबाद) अब 12 मार्च से 26 मार्च 2026 तक हर गुरुवार को, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 03379 (धनबाद-एलटीटी) 10 मार्च से 24 मार्च 2026 तक हर मंगलवार को चलेगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रक्सौल, सहरसा और धनबाद रूट की इन सभी विस्तारित ट्रेनों के समय और पूर्व-निर्धारित ठहराव (स्टॉपेज) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकारी अस्पताल भरोसे मरीज

- ठाणे जिले में 47,505 मरीज़ हुए ठीक
- जनवरी 2025 और जनवरी 2026 के बीच 14,419 बड़ी और 33,086 छोटी सर्जरी की गई

ठाणे। जिले के सरकारी अस्पतालों ने मरीजों के भारी दबाव के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच इन अस्पतालों में कुल 47,505 सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं, जिनमें 14,419 बड़ी और 33,086 छोटी सर्जरी शामिल हैं। इस शानदार रिकॉर्ड में सिविल अस्पताल ठाणे 4,341 बड़ी सर्जरी के साथ गंभीर मरीजों के इलाज में सबसे आगे रहा है। इसके अलावा, सेंट्रल अस्पताल उल्हासनगर-3 में 2,705 और उप-जिला अस्पताल भिवंडी में 2,643 बड़ी सर्जरी की गईं। वहीं, छोटी सर्जरी (माइनर ऑपरेशन) के मामले में भिवंडी अस्पताल 12,610 ऑपरेशनों के साथ शीर्ष पर रहा।

ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच बेहतरीन तालमेल

शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ जिले के ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत नींव देखने को मिली है। शाहपुर उप-जिला अस्पताल के अलावा बदलापुर, अंबरनाथ, मुरबाड, गोवेली और टोकवडे जैसे ग्रामीण अस्पतालों में भी सैकड़ों सर्जरी सफलतापूर्वक अंजाम दी गईं। स्वास्थ्य विभाग ने एक सुव्यवस्थित प्रणाली तैयार की है, जिसके तहत मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर स्थिति में तुरंत उच्च-स्तरीय केंद्रों (हायर-लेवल सेंटर) में रेफर किया जाता है। इस शानदार रेफरल सिस्टम की बदौलत ही ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतरीन संतुलन बन पाया है।

अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम पर सख्त हुई मनपा

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

उल्हासनगर शहर की मुख्य सड़कों और फुटपाथों पर बेतरतीब ढंग से खड़े दोपहिया और चार पहिया वाहनों के कारण लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम की शिकायतों को महानगरपालिका ने गंभीरता से लिया है। आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की ओर से मिल रही बढ़ती शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, उल्हासनगर मनपा ने अब अवैध रूप से पार्क किए गए इन वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णायक फैसला किया है।

मनपा और यातायात पुलिस का चलेगा संयुक्त विशेष अभियान

शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए मनपा आयुक्त मनीषा अव्हाले के आदेशानुसार एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण के मार्गदर्शन में होने वाली इस संयुक्त कार्रवाई में शहर का यातायात (ट्रैफिक) विभाग, स्थानीय पुलिस स्टेशन, चारों वार्ड समितियों के सहायक आयुक्त और मनपा के नोडल अधिकारी गणेश शिम्पी मिलकर हिस्सा लेंगे। इस टीम का मुख्य उद्देश्य शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है।

लावारिस वाहनों पर होगी नियमित कार्रवाई

नगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि मुख्य सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से खड़े किए गए और लावारिस छोड़े गए वाहनों के खिलाफ अब नियमित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, मनपा प्रशासन ने शहर के सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों को किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क पर अवैध रूप से पार्क न करें।

पश्चिम रेलवे ने की कबाड़ से कमाई

मिशन जीरो स्क्रैप के तहत स्क्रैप बिक्री में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा किया पार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्क्रैप (कबाड़) निपटान के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह बड़ी सफलता 'मिशन जीरो स्क्रैप' के तहत पश्चिम रेलवे की उस दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य अपने सभी प्रतिष्ठानों और इकाइयों को पूरी तरह से कबाड़-मुक्त और स्वच्छ बनाना है।

पिछले वर्ष की तुलना में 5 सप्ताह पहले हासिल किया मुकाम

इस शानदार उपलब्धि की सबसे खास बात यह है कि पश्चिम रेलवे ने इसे पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) की तुलना में पूरे 5 सप्ताह पहले ही हासिल कर लिया है (पिछले वर्ष यह लक्ष्य 21 मार्च 2025 को प्राप्त हुआ था)। यह सफलता पश्चिम रेलवे के कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन, साफ-सफाई (हाउसकीपिंग) पर विशेष ध्यान और बेकार हो चुकी सामग्री की समय पर पहचान कर उसके निपटान की बेहतरीन रणनीति का परिणाम है।

रेलवे बोर्ड के लक्ष्य से काफी आगे, 506.63 करोड़ की बिक्री

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) विनीत अभिषेक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्क्रैप बिक्री का लक्ष्य 470 करोड़ रुपये निर्धारित किया था। लेकिन पश्चिम रेलवे ने बेहतरीन कार्यप्रणाली अपनाते हुए 17 फरवरी 2026 तक ही कुल 506.63 करोड़ रुपये की बंपर स्क्रैप बिक्री दर्ज कर ली है, जो तय लक्ष्य से काफी अधिक है।

मुंबई लोकल बनी मुंबई की लाइफलाइन

वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य रेल से 1373 मिलियन से अधिक यात्रियों ने किया सफर

मुंबई। चालू वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी 2026 तक) में मध्य रेल ने यात्री परिवहन के क्षेत्र में एक शानदार रिकॉर्ड कायम किया है। इस अवधि के दौरान मध्य रेल ने कुल 1373.39 मिलियन यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया है। यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि (1348.33 मिलियन यात्री) की तुलना में 1.86% की वृद्धि को दर्शाता है।

यात्रियों की संख्या में यह वृद्धि उपनगरीय (लोकल) और गैर-उपनगरीय (मेल/एक्सप्रेस) दोनों खंडों में देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में उपनगरीय ट्रेनों में सफर करने वालों की संख्या बढ़कर 1201.93 मिलियन हो गई है, जो पिछले वर्ष 1187.92 मिलियन थी। वहीं, मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर जैसी गैर-उपनगरीय ट्रेनों में 171.46 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की। अकेले जनवरी 2026 की बात करें, तो कुल 146.29 मिलियन यात्रियों ने सफर किया, जिसमें मुंबई उपनगरीय लाइन के 127.12 मिलियन और पुणे उपनगरीय लाइन के 1.96 मिलियन यात्री शामिल हैं।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

मेष व्यवसाय ठीक चलेगा। पुराने मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी। व्यय होगा। प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में नए अनुबंध लाभकारी रहेंगे। परिश्रम का अनुकूल फल मिलेगा। परिजनों के स्वास्थ्य और सुविधाओं की ओर ध्यान दें।

वृष विवाद से क्लेश होगा। फालतू खर्च होगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है। जोखिम न लें। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्ति के योग हैं। सावधानी व सतर्कता से व्यापारिक अनुबंध करें। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा।

मिथुन बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। जोखिम न उठाएं। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर मिलेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

कर्क मेहनत का फल मिलेगा। योजना फलीभूत होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्ज से दूर रहना चाहिए। खर्च में कमी होगी। कानूनी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होने की संभावना है। प्रतिष्ठितजनों से मेल-जोल बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। रोजगार मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ संभव है। जोखिम न लें। धर्म के कार्यों में रुचि आपके मनोबल को ऊंचा करेगी। मिलनसारिता व धैर्यवान प्रवृत्ति जीवन में आनंद का संचार करेगी। कई दिनों से रुका पैसा मिल सकेगा।

कन्या चोट व रोग से बचें। कानूनी अड़चन दूर होगी। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। क्रय-विक्रय के कार्यों में लाभ होगा। योजनाएं बनेंगी। उच्च और बौद्धिक वर्ग में विशेष सम्मान प्राप्त होगा। भाइयों से अनबन हो सकती है।

तुला कुसंगति से हानि होगी। वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। वाणी परो नियंत्रण रखें, जोखिम न लें। परेशानियों का मुकाबला करके भी लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। व्यापारिक लाभ होगा। संतान के प्रति झुकाव बढ़ेगा। शिक्षा व ज्ञान में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रमाद न करें। जायदाद संबंधी समस्या सुलझने के आसार बनेंगे। अनुकूल समाचार मिलेंगे तथा दिन आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। नए संबंध लाभदायी सिद्ध होंगे।

धनु किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। लाभ होगा। धन संचय की बात बनेगी। परिवार के कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है। रुका कार्य होने से प्रसन्नाता होगी। आर्थिक सलाह उपयोगी रहेगी। कर्ज की चिंता कम होगी।

मकर अति व्यस्तता रहेगी। बुरी खबर मिल सकती है। दौड़धूप अधिक होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। थकान रहेगी। व्यापार-व्यवसाय संतोषप्रद रहेगा। आपसी संबंधों को महत्व दें। अल्प परिश्रम से ही लाभ होने की संभावना है। खर्चों में कमी करने का प्रयास करें।

कुंभ संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। धैर्य एवं शांति से वाद-विवादों से निपट सकेंगे। दुस्साहस न करें। नए विचार, योजना पर चर्चा होगी। स्वयं की प्रतिष्ठा व सम्मान के अनुरूप कार्य हो सकेंगे।

मीन प्रसन्नता रहेगी। संतान की शिक्षा की चिंता समाप्त होगी। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। महत्व के कार्य को समय पर करें। व्यावसायिक श्रेष्ठता का लाभ मिलेगा। मेहनत का फल कम मिलेगा। कार्य की प्रशंसा होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी।

जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31: वर्ष 2026 में अचानक बदल सकती है किस्मत

प्रियंका जैन
9769994439

यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो अंक ज्योतिष के अनुसार आपका संबंध राहु से माना जाता है। राहु को अचानक परिवर्तन, असामान्य सोच, जोखिम उठाने की क्षमता और अप्रत्याशित सफलता का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 इन तारीखों में जन्मे लोगों के लिए बड़े अवसरों और निर्णायक बदलावों का संकेत दे रहा है। लंबे समय से अटके काम गति पकड़ सकते हैं और मेहनत का परिणाम अचानक सामने आ सकता है, लेकिन इस दौरान संयम और सजगता बेहद जरूरी रहेगी।

4 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह वर्ष रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। आपकी मेहनत रंग ला सकती है, हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। 13 तारीख को जन्मे जातकों को शुरुआत में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष के अंत तक बड़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक दबाव कम होने के संकेत हैं। 22 तारीख, जिसे 'मास्टर नंबर' माना जाता है, वालों के लिए 2026 नेतृत्व और बड़ी जिम्मेदारी का वर्ष साबित हो सकता है। कार्यस्थल या सामाजिक जीवन में उन्नति के अवसर बन सकते हैं। 31 तारीख को जन्मे लोगों के लिए व्यापार और विस्तार के लिहाज से यह साल महत्वपूर्ण रहेगा, हालांकि बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक होगा।

इन तारीखों पर जन्मे कई दिग्गजों ने अपने क्षेत्र में असाधारण पहचान बनाई है। जैसे Atal Bihari Vajpayee (22 दिसंबर), Barack Obama (4 अगस्त), Kishore Kumar (4 अगस्त) और Preity Zinta (31 जनवरी)। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि राहु की ऊर्जा व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिलाने की क्षमता रखती है। अंक ज्योतिष के अनुसार 22, 31, 40, 49 और 58वां वर्ष विशेष उपलब्धियां दिला सकता है, जबकि 13, 26, 35 और 44वें वर्ष में स्वास्थ्य और निवेश को लेकर सावधानी बरतना बेहतर रहता है। स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग अचानक फैसले लेने वाले, तकनीक और नए प्रयोगों के शौकीन तथा तेज सोच वाले होते हैं। हालांकि एक साथ कई योजनाएं बनाना और फोकस खो देना प्रगति में बाधा बन सकता है।

वर्ष 2026 में अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए। दिखावे या बाहरी आकर्षण के कारण लिया गया निर्णय छवि और आर्थिक स्थिति दोनों को प्रभावित कर सकता है। संयम, स्पष्ट लक्ष्य और संतुलित निर्णय ही इस वर्ष को वास्तविक सफलता में बदल सकते हैं।

94300 हेक्टेयर में हो रही प्राकृतिक खेती

योगी सरकार का एक लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य

प्राकृतिक खेती विस्तार के लिए 298 करोड़ रुपये स्वीकृत

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 298 करोड़ रुपये की विस्तार योजना को आगे बढ़ाया है। राज्य सरकार के अनुसार, प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब तक लगभग 94,300 हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जा चुका है, जिसे शीघ्र ही एक लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कम होगी रसायन पर निर्भरता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करते हुए टिकाऊ कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार के अनुसार, निर्धारित बजट और चरणबद्ध क्रियान्वयन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक खेती के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य जारी है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम

सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जनपदों में कुल 23,500 हेक्टेयर क्षेत्र में गो-आधारित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कम वर्षा और जल संकट से प्रभावित इस क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को जलधारण क्षमता बढ़ाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है।

जीवामृत, घनजीवामृत से हुआ सुधार

राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार, जीवामृत और घनजीवामृत जैसे जैविक घोलों के प्रयोग से मिट्टी की संरचना सुदृढ़ होती है तथा रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता घटती है। इससे उत्पादन लागत में कमी आने और किसानों की आय बढ़ने की संभावना जताई गई है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर

प्राकृतिक खेती को मुख्यधारा में लाने के लिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विभिन्न जनपदों में कार्यशालाएं और प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित कर किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का दावा है कि रासायनिक इनपुट में कमी से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध होगा। साथ ही, प्राकृतिक उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रधर्म के सच्चे उपासक थे छत्रपति : योगी आदित्यनाथ

जयंती पर मुख्यमंत्री ने किया नमन, कहा-शिवाजी महाराज का जीवन प्रेरणादायी

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किए गए संदेश में शिवाजी महाराज को सनातन संस्कृति का अप्रतिम रक्षक और राष्ट्रधर्म का उपासक बताया। उन्होंने कहा कि 'हिंदवी स्वराज' की स्थापना कर शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान, साहस और सुशासन की ऐसी परंपरा स्थापित की, जो भारतीय इतिहास में प्रेरणा का स्थायी स्रोत बनी हुई है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि शिवाजी महाराज का त्याग, पराक्रम और राष्ट्रनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी स्वराज और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का उनका संकल्प भारतीय समाज को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों से शिवाजी महाराज के जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान भी किया।

बिहार के 42 विधायकों ने छिपाई जानकारी!

चुनावी शपथपत्र में नहीं दी गई सही जानकारी, मतदान में भी धांधली का आरोप

पटना हाई कोर्ट ने सभी विधायकों को नोटिस जारी करते हुए मांगा हलफनामा

एजेंसी । पटना

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष सहित 42 विधायकों को नोटिस जारी कर चुनावी शपथपत्रों में कथित त्रुटियों और अनियमितताओं के संबंध में जवाब तलब किया है। न्यायालय ने संबंधित जनप्रतिनिधियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दस्तावेजी साक्ष्य देने का निर्देश

यह याचिकाएं उन प्रत्याशियों की ओर से दायर की गई हैं, जिन्हें संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पराजय का सामना करना पड़ा था। प्रारंभिक सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने सभी 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए उनके पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।

ऊर्जा मंत्री को भी देना होगा जवाब

नोटिस प्राप्त करने वालों में ऊर्जा सह-वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद तथा गोह (गया) से विधायक अमरेंद्र प्रसाद के नाम शामिल हैं।

विधानसभा अध्यक्ष को भी नोटिस

नोटिस पाने वालों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के अलावा सत्ता और विपक्ष के कई विधायक शामिल हैं। न्यायालय में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि कुछ विजयी प्रत्याशियों ने नामांकन के समय प्रस्तुत हलफनामों में तथ्यों को पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया। कुछ याचिकाओं में मतदान प्रक्रिया में अनियमितता के भी आरोप लगाए गए हैं।

नहर में गिरी कार, युवा बेटे समेत दंपति की मौत

रूरा-सैफई मार्ग पर गंग नहर में हुआ हादसा

एजेंसी । औरेया

जनपद के अछल्दा थाना क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे में एक कार नहर में गिर गई, जिससे दंपति और उनके पुत्र सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना रूरा-सैफई मार्ग पर तुरुकपुर गांव के समीप स्थित निचली गंग नहर में हुई। गुरुवार सुबह लगभग सात बजे राहगीरों ने नहर में कार के टायर दिखाई देने पर अनहोनी की आशंका जताई और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी पंकज मिश्रा के नेतृत्व में बचाव अभियान शुरू किया गया। ग्रामीणों की सहायता से ट्रैक्टर की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया।

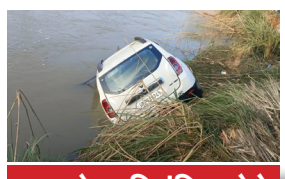

कार के अनियंत्रित होने की आशंका

जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि घटना की सूचना डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। मृतकों की पहचान बाबरपुर निवासी राजीव कुमार पोरवाल (60), उनके पुत्र शिवम (27) और पत्नी मधु गुप्ता (55) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार राजीव कुमार पोरवाल भरथना क्षेत्र में दाल व्यापार से जुड़े थे। क्षेत्राधिकारी बिधूना पुनीत मिश्रा के अनुसार प्रथम दृष्टया वाहन के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने की संभावना है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

वाराणसीः पांच सरकारी और दो निजी क्रूज दे रहे सेवा

विधान परिषद में सपा सदस्य के सवाल पर मंत्री ने दिया जवाब

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान वाराणसी में गंगा नदी पर संचालित क्रूज सेवाओं को लेकर प्रश्नोत्तर हुआ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सदन में उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर स्थिति स्पष्ट की। समाजवादी पार्टी के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी में सरकारी एवं निजी क्रूजों की संख्या, उनके संचालन मानक तथा संबंधित सूचनाएं सदन पटल पर रखने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन पर मंत्री ने बताया कि 6 दिसंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर संबंधित विधेयक पारित किया गया और परिवहन विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया।

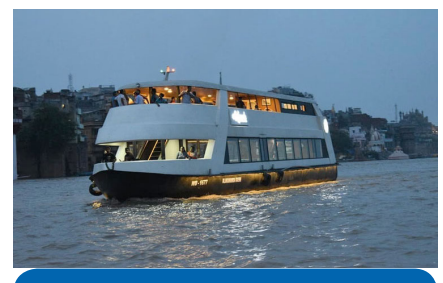

निर्धारित मानकों के हिसाब से हो रहा संचालन

मंत्री ने उत्तर देते हुए बताया कि वाराणसी में वर्तमान में 5 सरकारी और 2 निजी क्रूज संचालित हैं। इनका संचालन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संचालन संबंधी दिशा-निर्देश और नियामकीय प्रावधान लागू हैं तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध है।

17,27,52,631 टूरिस्ट आए काशी धाम

मंत्री ने पर्यटन से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व वाराणसी में 5,44,355 भारतीय और 3,34,860 विदेशी पर्यटक दर्ज किए गए थे, जबकि हाल के वर्षों में यह संख्या बढ़कर 17,27,52,631 से अधिक हो चुकी है।

उन्हे हस्तिनापुर की नहीं, दुर्योधन की चिंता थीः मैथिली ठाकुर

2005 के पहले का हवाला देते हुए विपक्ष पर साधा निशाना

एजेंसी । पटना

विधायक मैथिली ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले का बिहार महाभारत के धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर जैसा था, जहां शासन तो था लेकिन व्यवस्था देखने और सुधारने की इच्छाशक्ति नहीं थी। उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्हें हस्तिनापुर की नहीं, केवल दुर्योधन की चिंता थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता उस दौर के साक्षी भी रहे हैं और सत्ता का हिस्सा भी, इसलिए उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। जनता भले भूल जाए, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूलता और न ही माफ करता है। वर्ष 2005 को बिहार के लिए ऐतिहासिक मोड़ बताते हुए उन्होंने कहा कि उस समय एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसका नाम है नीतीश कुमार।

> कहा- धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर जैसा था पहले वाला बिहार

कागजों पर चलते थे विद्यालय

सदन में शिक्षा बजट पर बोलते हुए मैथिली ठाकुर ने बिहार में आए बदलाव के लिए सीएम नीतीश की तारीफ की। कहा, एक समय था जब सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर थी, शिक्षक वेतन के लिए भटकते थे और बच्चों को मध्यान्ह भोजन तक नसीब नहीं होता था। कागज़ों पर विद्यालय चलते थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और थी।

मॉडल बन गई साइकिल योजना

सीएम साइकिल योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे सरकार की ऐतिहासिक पहल करार दिया। कहा कि पहले जहां लड़कियाँ स्कूल तक नहीं पहुंच पाती थीं, वहीं साइकिल मिलने के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं विद्यालय जाने लगीं।

अंधकार से प्रकाश की ओर बिहार

मैथिली ठाकुर ने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, शराबबंदी और महिला सुरक्षा से जुड़े कड़े कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने बेटियों को आत्मविश्वास और सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने समापन करते हुए कहा कि बिहार ने अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर और जंगलराज से सुशासन की ओर यात्रा की है।

व्यापार जगत

देश में बनेगा दुर्लभ स्थाई चुंबक

कोयला मंत्री ने कहा- वित्तीय वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा उत्पादन

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री G. Kishan Reddy ने घोषणा की है कि भारत में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (Rare Earth Permanent Magnets – REPM) का घरेलू उत्पादन चालू वर्ष के अंत तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), पवन ऊर्जा और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है।

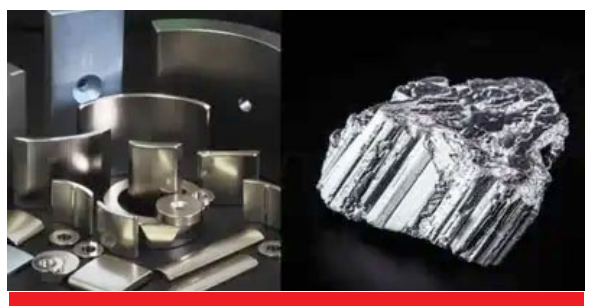

अभी 95% हिस्सा हो रहा आयात

राजधानी में उद्योग संगठन Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (फिक्की) और खान मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' रणनीति के तहत केंद्र सरकार दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बहुस्तरीय नीति पर कार्य कर रही है। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकताओं का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है।

32000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना

मंत्री ने बताया कि 'राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन' के अंतर्गत लगभग 32,000 करोड़ रुपये के व्यय से व्यापक कार्ययोजना लागू की जा रही है। देशभर में 4,000 से अधिक अन्वेषण गतिविधियां प्रारंभ की जा चुकी हैं, जिनका उद्देश्य रणनीतिक खनिज भंडारों की पहचान और दोहन को गति देना है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को भी संस्थागत सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

ओडिशा, महाराष्ट्र में संयंत्र पार्क

मंत्री के अनुसार, गुजरात ने इस दिशा में प्रारंभिक पहल की है, जबकि आंध्र प्रदेश भी प्रसंस्करण अवसंरचना विकसित करने के लिए तैयार है। ओडिशा और महाराष्ट्र में भी महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र पार्क स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। खान मंत्रालय ने अन्वेषण ब्लॉकों की नीलामी के साथ-साथ पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) सुविधाओं को भी स्वीकृति प्रदान की है, ताकि संसाधनों का चक्रीय उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

AI में ₹10,00,000 करोड़ का निवेश करेगा जियो

रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की घोषणा

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि समूह की दूरसंचार इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स आगामी सात वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

डिजिटल कनेक्टिविटी में जियो की भूमिका महत्वपूर्ण

अंबानी ने कहा कि जियो ने देश में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार में भूमिका निभाई है और अब कंपनी एआई-आधारित सेवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी।

राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इंपैक्ट समिट' में संबोधन के दौरान अंबानी ने कहा कि यह निवेश दीर्घकालिक अवसंरचना निर्माण और डिजिटल क्षमताओं के विस्तार पर केंद्रित होगा। उनके अनुसार यह पूंजी सट्टा या अल्पकालिक लाभ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्र निर्माण की दिशा में नियोजित की जा रही है।

वैश्विक स्तर पर एआई की बढ़ रही मांग

उन्होंने कहा कि एआई वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के रूप में उभर रही है। उनके अनुसार इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती प्रतिभा नहीं, बल्कि उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग अवसंरचना और गीगावाट स्तर के डेटा सेंटर स्थापित करने की लागत है। प्रस्तावित निवेश का एक प्रमुख हिस्सा इसी अवसंरचना सुदृढ़ीकरण पर व्यय किया जाएगा।

विकसित राष्ट्र की स्थापना में अहम भूमिका

उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में एआई को एक प्रमुख चालक के रूप में स्थापित कर सकता है। उनके अनुसार, सुविचारित उपयोग के साथ एआई उत्पादकता वृद्धि, आर्थिक समावेशन और सामाजिक विकास को गति दे सकती है। कार्यक्रम के दौरान अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का उल्लेख करते हुए एआई क्षेत्र में नीति समर्थन और संस्थागत पहल की सराहना की।

बैंक धोखाधड़ीः 26 फरवरी को अनिल अंबानी तलब

एजेंसी । नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को नया समन जारी कर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। एजेंसी के अनुसार पूर्व निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने के कारण यह नया समन जारी किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

पत्नी टीना अंबानी को भी समन

इस प्रकरण में अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को भी समन जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें पूर्व में भी पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था, किंतु वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुईं। एजेंसी की ओर से अगली उपस्थिति तिथि के संबंध में आधिकारिक जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है।

न्यूयार्क से जुड़ी संपत्ति की हो रही जांच

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार पूछताछ का एक पहलू न्यूयॉर्क के मैनहट्टन क्षेत्र में स्थित एक आवासीय संपत्ति के कथित लेन-देन से संबंधित है। इस मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान हुई एक संपत्ति बिक्री की भी जांच की जा रही है।

वैश्विक तनाव के बीच बाजार में गिरावट

सेंसेक्स 1,236 और निफ्टी 365 अंक नीचे

नई दिल्ली। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार में व्यापक बिकवाली देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख सूचकांकों में तेज गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर निवेशकों की धारणा पर पड़ा।

30 शेयरों पर आधारित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 1,236.11 अंक यानी 1.48 प्रतिशत गिरकर 82,498.14 के स्तर पर बंद हुआ।

प्रमुख शेयरों में दबाव

सेंसेक्स की कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अडाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, आईटीसी और पावर ग्रिड के शेयरों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखी गई। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड 1.02 प्रतिशत चढ़कर 71.07 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

23 फरवरी से खुलेगा अकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर का एसएमई आईपीओ

एजेंसी । मुंबई

ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और अनुकूलित बिजली समाधान बनाने वाली कंपनी अकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित एसएमई प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 16 फरवरी 2026 को हरियाणा के कंपनी रजिस्ट्रार के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) दाखिल किया है। कंपनी का यह निर्गम 100 प्रतिशत बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के तहत लाया जा रहा है, जिसमें 10 अंकित मूल्य वाले 55,62,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल है। कुल निर्गम में से 2,82,000 शेयर मार्केट मेकर के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जबकि शेष 52,80,000 शेयर योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत, गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत आवंटित किए जाएंगे। यह आईपीओ सोमवार, 23 फरवरी 2026 को सदस्यता के लिए खुलेगा और बुधवार, 25 फरवरी 2026 को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 20 फरवरी 2026 को खुलेगी और उसी दिन बंद होगी। प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है। कंपनी के प्रवर्तकों में श्री प्रदीप कुमार वर्मा और श्रीमती शालिनी सिंह शामिल हैं। इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कार्य कर रही है। मूल्य बैंड और बोली का दायरा कंपनी द्वारा बुक रनिंग लीड मैनेजर के परामर्श से तय किया जाएगा और इश्यू खुलने से पहले घोषित किया जाएगा।

बड़का-बड़का टीम के 'बैंड' बजा रहा जिम्बाब्वे

- ऑस्ट्रेलिया के बाद अब श्रीलंका को भी रौंदा, 6 विकेट से हराया
- जिम्बाब्वे ने ग्रुप स्टेज में अजेय रहते हुए सुपर-8 के लिए धमाकेदार एंट्री मारी

एजेंसी । कोलंबो

कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में गुरुवार (19 फरवरी) को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मुकाबले में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर क्रिकेट जगत को एक और बड़ा सरप्राइज दिया है। विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को रौंदने के बाद अब सह-मेजबान श्रीलंका पर यह शानदार जीत दर्ज कर जिम्बाब्वे ने ग्रुप स्टेज में अपना अजेय अभियान जारी रखा है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही टीम ने सुपर-8 में अपनी धमाकेदार एंट्री पक्की कर ली है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 178 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। टीम को पावरप्ले में 61 रनों की अच्छी शुरुआत मिली, जिसमें कुसल परेरा ने 14 गेंदों पर 22 रन का योगदान दिया। सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने शानदार लय दिखाते हुए 41 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 62 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं, मध्यक्रम में पावन रत्नायके ने महज 25 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों के साथ 44 रन बनाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।

जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का अनुशासित प्रदर्शन

श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अंतिम ओवरों में खुलकर न खेलने देने का श्रेय जिम्बाब्वे के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण और चुस्त फील्डिंग को जाता है। अनुभवी लेग स्पिनर ग्रीम क्रेमर सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 27 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए। उनके अलावा तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपनी गति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 38 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि ब्रैड इवांस को भी 2 और रयान बर्ल को 1 सफलता मिली। पारी के अंत में दुनिथ वेलालगे (नाबाद 15) की बदौलत श्रीलंका 178 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका।

कप्तान सिकंदर रजा की तूफानी पारी ने पलटा मैच

इस रन चेज में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की आक्रामक बल्लेबाजी रही। रजा ने क्रीज पर आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और मात्र 26 गेंदों में 4 गगनचुंबी छक्कों और 2 चौकों की मदद से 45 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस बेखौफ बल्लेबाजी ने मैच का पूरा पासा जिम्बाब्वे के पक्ष में पलट दिया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की आक्रामक शुरुआत

179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए और पावरप्ले में तेजी से 55 रन बटोरे। सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने एक छोर मजबूती से थामे रखा और 48 गेंदों में 8 चौकों की मदद से नाबाद 63 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। मध्यक्रम में तदिवानाशे मारुमनी (34 रन) और रयान बर्ल (23 रन) ने बेनेट का अच्छा साथ निभाया और रन गति को धीमा नहीं पड़ने दिया।

आखिरी ओवर का रोमांच और जिम्बाब्वे की ऐतिहासिक जीत

मैच के आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को जीत के लिए महज 8 रनों की दरकार थी और श्रीलंका की तरफ से महीश तीक्षणा गेंदबाजी कर रहे थे। टोनी मुनयोंगा ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर श्रीलंकाई प्रशंसकों को खामोश कर दिया। इसके बाद ब्रायन बेनेट ने एक्स्ट्रा कवर की ओर बेहतरीन चौका लगाकर 19.3 ओवरों में ही अपनी टीम को जीत दिला दी। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में जिम्बाब्वे का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज है। 2024 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने से चूकने वाली इस टीम ने 2026 में शानदार वापसी करते हुए ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसी टीमों को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

आ अब लौट चलें...

पाल्लेकेले। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 विश्व कप में अपने निराशाजनक अभियान का अंत ओमान के खिलाफ करेगी। ग्रुप स्टेज के दो अहम मैच हारने के बाद निराश ऑस्ट्रेलियाई टीम इस कमजोर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज करके टूर्नामेंट से सकारात्मक विदाई लेने की कोशिश करेगी। छह वनडे और एक टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर चुकी इस चैंपियन टीम के लिए यह टूर्नामेंट किसी झटके से कम नहीं रहा है।

बारिश ने तोड़ी उम्मीदें, सुपर-8 की दौड़ से बाहर

ऑस्ट्रेलियाई टीम के अगले दौर (सुपर-8) में पहुंचने की बची-खुची उम्मीदें मंगलवार को कैंडी में उस वक्त खत्म हो गईं, जब जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच खेला जाने वाला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इस रद्द हुए मैच से जिम्बाब्वे को एक अहम अंक मिला, जिसकी बदौलत उसने श्रीलंका के साथ ग्रुप-बी से सुपर-8 में प्रवेश कर लिया और ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गया।

लचर प्रदर्शन की होगी समीक्षा, 2009 के बाद पहली बार ग्रुप स्टेज से बाहर

चोटिल खिलाड़ियों और खराब फॉर्म से जूझ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी में पूरी तरह बेअसर दिखी, तो वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ उसे बड़े उलटफेर का शिकार होना पड़ा। खराब खेल और चयन के विवादित फैसलों के चलते 2009 के बाद यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सका। इसी लचर प्रदर्शन के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने टीम के स्वदेश लौटने पर गहन समीक्षा करने का फैसला किया है।

तेज गेंदबाजों की कमी खली, अब 2028 के विश्व कप पर होगी नजर

पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड और मिशेल स्टार्क की स्टार तेज गेंदबाजी तिकड़ी के बिना टूर्नामेंट में उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को शुरुआत में खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हालांकि, जिम्बाब्वे से हार के बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। अब टीम स्वदेश लौटकर 2028 में अपने घरेलू मैदान पर होने वाले टी20 विश्व कप के लिए नई रणनीति बनाने पर काम करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी अब 30 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं।

ओमान के खिलाफ जीत का प्रबल दावेदार है ऑस्ट्रेलिया

अपने निराशाजनक अभियान के बावजूद, ओमान के खिलाफ इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीत का प्रबल दावेदार है। इस टूर्नामेंट में अब तक खेले गए तीन मैचों में से ऑस्ट्रेलिया ने केवल आयरलैंड (67 रन से) के खिलाफ जीत दर्ज की है। इससे पहले, अमेरिका में खेले गए 2024 टी20 विश्व कप में भी ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रनों से हराया था।

न्यूज ब्रीफ

नागल की हार के साथ एकल में भारतीय चुनौती खत्म

नई दिल्ली। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल की हार के साथ दिल्ली ओपन के एकल में गुरुवार को भारतीय चुनौती खत्म हो गई। नागल को अंतिम-16 में इटली के फेडरिको सिना के हाथों 6-4, 6-4 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अन्य मुकाबलों में ब्रिटेन के जे क्लार्क ने इटली के अजेकजेंडर बिंदा को 6-4, 6-4 से, बेल्जियम के माइकल गीटर्स ने पोलैंड के डनिएल मिचल्स्की को 7-6, 6-4 से और जापान के रियो नोगुची ने बुल्गारिया के दिमित्र कुजमानोव को 6-4, 6-3 से पराजित किया।

11 साल का 'वनवास' खत्म

नई दिल्ली। कर्नाटक ने उत्तराखंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच ड्रॉ होने के बावजूद पहली पारी की विशाल बढ़त के आधार पर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। पूरे 11 साल के लंबे अंतराल के बाद कर्नाटक इस खिताबी मुकाबले में पहुंचा है। अब 24 फरवरी से हुबली में होने वाले फाइनल मैच में उसका सामना जम्मू-कश्मीर की टीम से होगा। मैच के पांचवें और आखिरी दिन कर्नाटक ने अपनी दूसरी पारी 323 रन पर समाप्त की, जिससे उसकी कुल बढ़त 826 रन हो गई। इसके जवाब में विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तराखंड की टीम ने शानदार संघर्ष दिखाया। एक समय 156 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद, अभय नेगी (नाबाद 57) और सचिन रावत (नाबाद 53) ने सातवें विकेट के लिए 104 रनों की अटूट साझेदारी कर मैच को ड्रॉ करा दिया। हालांकि, पहली पारी में मिली मजबूत बढ़त की बदौलत कर्नाटक फाइनल का टिकट कटाने में सफल रहा। यह फाइनल मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद खास होने वाला है। एक तरफ कर्नाटक की निगाहें अपने नौवें रणजी ट्रॉफी खिताब को जीतने पर होंगी, जो उसने आखिरी बार 2014-15 सीजन में आर विनय कुमार की कप्तानी में जीता था। वहीं दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर की टीम अपने क्रिकेट इतिहास के छह दशकों में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है और उसकी पूरी कोशिश अपने पहले ऐतिहासिक खिताब पर कब्जा जमाने की होगी।

जीतते-जीतते हार गई हरमनप्रीत की सेना

कैनबरा। कैनबरा में खेले गए दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार वापसी करते हुए भारतीय महिला टीम को 19 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 144 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की जीत की मजबूत नींव सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल और बेथ मूनी ने रखी। इन दोनों ने सपाट पिच का फायदा उठाते हुए पहले विकेट के लिए 14.5 ओवर में 128 रन जोड़े। यह भारत के खिलाफ महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एलिसा हीली और मूनी (115 रन) के नाम था। वोल ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 57 गेंदों में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 88 रन बनाए, जबकि मूनी ने 39 गेंदों में 46 रनों की समझदारी भरी पारी खेली।

होप के 'हौंक' से इटली ढेर

वेस्टइंडीज की इटली पर 42 रन से शानदार जीत

कोलकाता। कोलकाता में खेले गए टी20 विश्व कप के ग्रुप सी मुकाबले में वेस्टइंडीज ने गुरुवार को इटली को 42 रनों से हरा दिया। कप्तान शाई होप की शानदार बल्लेबाजी और तेज गेंदबाज शामार जोसेफ के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत कैरेबियाई टीम ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 165 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में इटली की पूरी टीम 18 ओवर में महज 123 रन पर ही सिमट गई। इस मुकाबले में कैरेबियाई तेज गेंदबाज शामार जोसेफ ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 30 रन देकर 4 अहम विकेट चटकाए और फील्डिंग में भी गजब की चुस्ती दिखाते हुए 4 कैच लपके। इसके साथ ही जोसेफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक ही मैच में चार विकेट लेने और चार कैच पकड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

बॉलीवुड

प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड करियर को लेकर किए खुलासे

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड सिनेमा पर भी राज कर रही हैं। प्रियंका की हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' 25 फरवरी को रिलीज हो रही है। हाल ही में प्रियंका ने अपनी फिल्म 'द ब्लफ' के अलावा अपने हॉलीवुड करियर को लेकर कई खुलासे किए हैं। साथ ही प्रियंका ने यह भी बताया कि उनके लिए 'द ब्लफ' क्यों खास है? प्रियंका चोपड़ा जोनस ने हॉलीवुड करियर में अपनी उन्नति के बारे में कहा, 'मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं सफलता के सबसे ऊपर पहुंच गई हूं, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है।' प्रियंका ने आगे कहा, 'जब मैं पहली बार हॉलीवुड आई थी, तब से मैंने कभी खुद को कमजोर नहीं महसूस किया। भले ही लोग मुझे जानते नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे पता था कि मैं क्या कर सकती हूं और मेरी क्या कीमत है। मेरा आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। हो सकता है मुझे कम मौके मिले हों या कम कामयाबी मिली हो, लेकिन मुझे अपने टैलेंट और मेहनत करने की ताकत पर हमेशा भरोसा रहा।'

किसकी तरह बनना चाहती हैं प्रियंका

प्रियंका ने कहा, 'मैं बहुत मेहनत करने वाली हूं। किसी भी रोल या किरदार को अच्छे से निभाने के लिए मैं बहुत समय और मेहनत लगाती हूं। लेकिन ये सोचना कि मैं सफलता की मंजिल पर पहुंच गई हूं? ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे आज भी लगता है कि मैं अभी वहां नहीं पहुंची। बहुत से शानदार लोग हैं, जिन्होंने कमाल का काम किया है और मैं भी उनके जैसा बनना चाहती हूं।' प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपनी नई फिल्म 'द ब्लफ' के बारे में कहा, "द ब्लफ' मेरी फिल्मों में एक नया बदलाव लाने वाली फिल्म है। मुझे लगता है कि यह मेरी फिल्मोग्राफी में, खासकर अंग्रेजी फिल्मों में, विविधता लाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। यह फिल्म संस्कृति और इतिहास की गहराई को छूती है, लेकिन साथ ही यह एक मजेदार, भावुक और रोमांचक समुद्री डाकू फिल्म भी है। इसमें ढेर सारा ड्रामा, एक्शन और भावनाएं हैं।'

कैसी फिल्में करना पसंद करती हैं प्रियंका

प्रियंका ने आगे बताया कि उन्हें कैसी फिल्में करना पसंद हैं। प्रियंका ने कहा, 'मुझे अलग-अलग तरह की कहानियां और जॉनर आजमाना बहुत पसंद है, इसलिए फिल्म 'द ब्लफ' को करके मुझे बहुत खुशी हुई।' फिल्म 'द ब्लफ' 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है।

'द केरल स्टोरी-2' का पैन-इंडिया प्लान, दो नई भाषाओं में ट्रेलर रिलीज

फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड' अब बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है। मेकर्स ने फिल्म को हिंदी के साथ-साथ तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज करने का फैसला लिया है। इसी के साथ इन भाषाओं में फिल्म के ट्रेलर भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे फिल्म का दायरा और व्यापक हो गया है। सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म अब क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हुए पैन-इंडिया दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाने जा रही है। फिल्म का उद्देश्य केवल हिंदी बेल्ट तक सीमित न रहकर साउथ भारतीय बाजारों में भी मजबूत पकड़ बनाना है। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कामाख्या नारायण सिंह ने किया है, जो अपनी संवेदनशील और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्म 'भोर' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली थी, जबकि उनकी डॉक्यूमेंट्री 'जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड' को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

हाल ही में रिलीज हुए हिंदी ट्रेलर को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। उनके किरदारों के पोस्टर पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं, जो कहानी की गंभीरता और भावनात्मक गहराई को दर्शाते हैं। मेकर्स का मानना है कि पहले भाग की सफलता और देशभर में उठी बहस को देखते हुए फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज करना जरूरी था, ताकि इसकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 'द केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड' 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

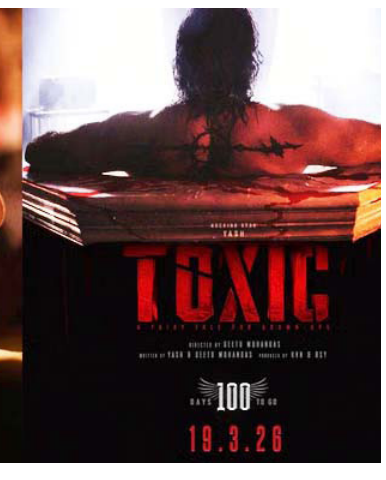

यश की 'टॉक्सिक' का नया पोस्टर जारी

अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का जहां दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, वहीं सुपरस्टार यश अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। केवीएन प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन गीतु मोहनदास ने किया है और इसकी रिलीज 19 मार्च को तय है। इसी बीच फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। पोस्टर में यश एक बर्फीले तूफान के बीच खड़े नजर आते हैं और बोतल से कुछ पीते दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने की बर्फ पर खून दिखाई दे रहा है, जो फिल्म के डार्क और इंटेंस माहौल की झलक देता है।

मुफ्त की रेवड़ियों पर कोर्ट की खरी-खरी

फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी । नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में बढ़ती 'मुफ्त की रेवड़ियों' (फ्रीबीज) की संस्कृति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारें सुबह से शाम तक लोगों को मुफ्त खाना, गैस और बिजली जैसी सुविधाएं बांटती रहेंगी, तो लोगों में काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। अदालत का मानना है कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना किसी भेदभाव के सभी को मुफ्त सुविधाएं बांटना सही दिशा नहीं है। बीते कुछ सालों में देश भर में यह चलन बढ़ा है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। सत्ताधारी दल इसे 'जन कल्याणकारी योजना' बताते हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां 'मुफ्त की रेवड़ियां' कह कर आलोचना करती हैं। केंद्र में बतौर विपक्षी पार्टी आलोचना करने वाली कांग्रेस अपनी सत्ता वाले राज्यों में खुल कर 'रेवड़ियां' बांटती है। उसी तरह केंद्र में खुल कर यह काम करने वाली भाजपा, राज्यों में कांग्रेस व अन्य पार्टियों का इसके लिए विरोध करती है।

मुफ्त सुविधाओं के बजाय रोजगार पर हो फोकस

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकारों को रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी। सीजेआई ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकारों को लोगों के लिए कमाई के रास्ते बनाने चाहिए ताकि वे अपनी इज्जत और आत्म-सम्मान के साथ जी सकें। अदालत ने सवाल उठाया कि जब सब कुछ एक ही जगह से मुफ्त मिलेगा, तो लोग काम क्यों करेंगे, और क्या हम भविष्य के लिए ऐसा ही आलसी देश बनाना चाहते हैं।

तमिलनाडु की मुफ्त बिजली योजना से जुड़ा है मामला

सुप्रीम कोर्ट की यह अहम टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। इस याचिका में 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी गई है, जिसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी शर्त के हर दो महीने में 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

चुनाव के समय घोषणाओं और राजस्व घाटे पर सवाल

अदालत ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के आस-पास अचानक मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की प्रवृत्ति को भी आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य पहले से ही राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं, फिर भी वे विकास कार्यों को नजरअंदाज करके मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। बेंच ने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को इस पर फिर से विचार करने की सलाह देते हुए कहा कि इस तरह की अनावश्यक उदारता देश के विकास में बड़ी रुकावट बन सकती है।

रेवड़ी कल्चर से बढ़ा देश का कर्ज

देश पर कुल सरकारी कर्ज करीब 270 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसमें लगभग 85-90 लाख करोड़ राज्य सरकारों का हिस्सा है। कई राज्यों में मुफ्त योजनाओं पर राजस्व का बड़ा भाग खर्च हो रहा है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है। पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और कृषि सब्सिडी पर राजस्व का लगभग 15-18% खर्च होता है और इसका कर्ज-से-GSDP अनुपात 46% से अधिक है, जो खतरे के स्तर से ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में OPS और नकद योजनाओं के कारण यह अनुपात 42% से अधिक है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी मुफ्त इलाज, नकद सहायता और राशन जैसी योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, जिससे कर्ज का स्तर 32-38% के बीच बना हुआ है। वहीं दिल्ली और कर्नाटक में कर्ज अनुपात अपेक्षाकृत कम (18-23%) है, लेकिन राजस्व घाटे का दबाव बढ़ रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसान, महिला और छात्र कल्याण योजनाओं पर बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को लेकर बहस तेज हो गई है।

नकद पैसा देने का चलन बढ़ा

पिछले कुछ वर्षों में राज्यों में सीधे नकद सहायता देने का चलन तेजी से बढ़ा है, खासकर महिलाओं को लक्षित योजनाओं के जरिए। चुनावी दौर में नई-नई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाएं घोषित की जा रही हैं। तमिलनाडु की 'कलैग्नार मगलिर उरीमई थोगाई' योजना के तहत 1.31 करोड़ महिलाओं को 1,000 प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, जिस पर सालाना लगभग 16,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। कर्नाटक की 'गृह लक्ष्मी योजना' में 1.15 करोड़ महिलाओं को 2,000 प्रतिमाह (करीब 17,500 करोड़ वार्षिक), जबकि मध्य प्रदेश की 'लाड़ली बहना योजना' में 1.26 करोड़ महिलाओं को 1,250 प्रतिमाह (लगभग 18,984 करोड़ सालाना) दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 'लाडली बहन योजना', हरियाणा की 'लाडो लक्ष्मी योजना' (2025) और हिमाचल प्रदेश की 'इंदिरा गांधी नारी सम्मान निधि' भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार भी भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना के जरिए सीधे खातों में धन हस्तांतरित कर रही है। इन योजनाओं पर जीडीपी और राज्यों के बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, जिससे राजकोषीय संतुलन और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर बहस तेज हो गई है।

तुष्टीकरण की नीति और कल्याणकारी योजनाओं में संतुलन

न्यायपालिका ने कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक तुष्टीकरण के बीच स्पष्ट रेखा खींचने पर जोर दिया है। अदालत ने टिप्पणी की कि जो लोग बिजली का बिल चुकाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें राहत देना एक उचित कल्याणकारी कदम है। लेकिन जो लोग भुगतान करने में पूरी तरह सक्षम हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच कोई फर्क किए बिना सबको मुफ्त सुविधाएं देना महज तुष्टीकरण की नीति है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर भारत में किस तरह की संस्कृति विकसित की जा रही है और यह सब कब तक चलेगा।

पूर्व में भी मुफ्त राशन को लेकर कोर्ट जता चुका है नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई पहली बार इस समस्या को नहीं उठाया है। 2022 में भी कोर्ट ने कुछ ऐसा ही कहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, रिजर्व बैंक, सत्ताधारी और विपक्षी दल, सबसे इस बारे में सलाह देने के लिए कहा था कि चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा 'रेवड़ियां' बांटने की बीमारी का क्या इलाज किया जाए। लेकिन, इलाज निकालने के बजाय मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल 12 फरवरी 2025 को भी कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त राशन मिलने के कारण लोग काम नहीं करना चाहते, जिससे समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के बजाय 'परजीवियों की जमात' खड़ी हो रही है। वहीं, 9 दिसंबर 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटे जाने पर केंद्र सरकार से सवाल किया था कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के बजाय आखिर कब तक इस तरह मुफ्त राशन बांटती रहेगी।

न्यूज़ ब्रीफ

2027 में जिनेवा में होगा एआई समिट

नई दिल्ली। स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन ने गुरुवार को घोषणा की कि स्विट्जरलैंड वर्ष 2027 में जिनेवा में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल नीति के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड की स्थिति मजबूत होगी और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि होगी। भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान स्विस पवेलियन में मीडिया से बातचीत करते हुए पार्मेलिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक को बेहतरीन बताया। दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय वार्ता भी की।

रामकृष्ण परमहंस के विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके महान विचार हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 19 फरवरी 1836 को हुआ था। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अध्यात्म और साधना को जिस प्रकार जीवनशक्ति के रूप में स्थापित किया, वह हर युग में मानवता का कल्याण करता रहेगा। उनके सुविचार और संदेश सदैव प्रेरणापुंज बने रहेंगे। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करने वाले रामकृष्ण परमहंस धर्मों के बीच सामंजस्य पर अपने उपदेशों के लिए जाने जाते हैं। आगे चलकर रामकृष्ण और उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।

दुरईसामी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ दाखिल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेता सैदाई एस. दुरईसामी की चुनाव याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में दुरईसामी की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। दुरईसामी 2011 के विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट पर स्टालिन से 2,739 वोटों से हार गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को निर्धारित व्यय सीमा से अधिक धन वितरित किया गया था, साथ ही पूरक मतगणना भी कराई गई थी।

बिरयानी रेस्टोरेंट ने डकार लिए 70,000 करोड़

- 2019-20 से अब तक कैश बिल डिलीट कर करोड़ों की टैक्स चोरी
- एआई से बिलिंग सॉफ्टवेयर की जांच में खुलासा

एजेंसी । हैदराबाद/बेंगलुरु

हैदराबाद में एक बिरयानी रेस्टोरेंट चेन की जांच करते हुए आयकर विभाग ने देशभर में फैले एक विशाल टैक्स चोरी घोटाले का भंडाफोड़ किया है। विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक रेस्टोरेंट्स द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपये की बिरयानी बिक्री को छिपाया गया है। यह बड़ा घोटाला बिलिंग सॉफ्टवेयर में हेरफेर करके अंजाम दिया जा रहा था।

1.77 लाख रेस्टोरेंट्स का 60 टीबी डेटा और एआई का इस्तेमाल

हैदराबाद जांच यूनिट ने इस घोटाले की गहराई तक जाने के लिए हाई-कैपेसिटी सिस्टम और जेनरेटिव एआई (AI) टूल्स का सहारा लिया। अधिकारियों ने देशभर के करीब 1.77 लाख रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल हो रहे एक खास बिलिंग सॉफ्टवेयर के 60 टेराबाइट ट्रांजैक्शन डेटा का विश्लेषण किया। बाजार के लगभग 10% हिस्से को कंट्रोल करने वाले इस सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड्स (जैसे GST नंबर) के जरिए रेस्टोरेंट्स की पहचान सुनिश्चित की गई।

कैश बिल डिलीट कर ऐसे होता था टैक्स चोरी का खेल

आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट मालिक टैक्स बचाने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर का ही गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ग्राहकों से कार्ड, यूपीआई या नकद पेमेंट लेने के बाद वे सिस्टम से बिल डिलीट या एडिट कर देते थे। ट्रैक होने से बचने के लिए मुख्य रूप से नकद (कैश) बिलों को निशाना बनाया जाता था, या फिर किसी खास तारीख या पूरे 30 दिन का डेटा ही गायब कर दिया जाता था, ताकि इनकम टैक्स और जीएसटी की देनदारी कम दिखाई जा सके।

13,317 करोड़ रुपये के बिल बनने के बाद हुए डिलीट

डेटा की सघन जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 70,000 करोड़ रुपये की छिपाई गई कुल आय में से 13,317 करोड़ रुपये की एंट्री तो बिल जेनरेट होने के बाद डिलीट की गई थी। केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही 5,141 करोड़ रुपये की बिक्री छिपाई गई। यहां के 40 रेस्टोरेंट्स की फिजिकल और डिजिटल सैंपलिंग में ही करीब 400 करोड़ रुपये (कुल बिक्री का लगभग 27%) दबाने की पुष्टि हुई है। फिलहाल विभाग इस पर टैक्स और पेनल्टी की गणना कर रहा है।

5 राज्यों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी

टैक्स चोरी के इस बड़े खेल में 5 राज्य—तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे पाए गए। केवल डिलीट किए गए डेटा की बात करें तो कर्नाटक में 2,000 करोड़, तेलंगाना में 1,500 करोड़ और तमिलनाडु में 1,200 करोड़ रुपये के बिल गायब किए गए।

कुत्ते की कस्टडी पर तकरार

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पालतू रॉटवाइलर कुत्ते हेनरी की कस्टडी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने इस मामले में वकील जय अनंत देहादराई को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। महुआ मोइत्रा ने साकेत कोर्ट के दस नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमे साकेत कोर्ट ने उन्हें हर महीने दस दिनों के लिए हेनरी की कस्टडी देने से मना कर दिया था।

भारत-इजरायल ने रक्षा सहयोग के लिए किया एक और करार

- प्रधानमंत्री मोदी की तेल अवीव यात्रा से पहले हुआ समझौता

एजेंसी । नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 फरवरी से शुरू होने वाली दो दिवसीय इजरायल यात्रा से ठीक पहले दोनों देशों ने अपने रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने के उद्देश्य से भारत और इजरायल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

रक्षा कंपनियों के बीच संगोष्ठी और बी2बी बैठकों का आयोजन

इस समझौते की रूपरेखा इजरायल के रक्षा मंत्रालय (IMOD) के तहत काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय (SIBAT) की पहल पर तैयार हुई। SIBAT ने 'सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स' (SIDM) और भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर दोनों देशों की अग्रणी रक्षा कंपनियों के बीच एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी और बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) बैठकों का आयोजन किया।

टीएमसी में शामिल हुए भाजपा विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा

2024 में निर्दलीय लड़ा था लोकसभा चुनाव

पाला बदल

एजेंसी । कोलकाता

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दल-बदल की राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में कुर्सियांग से पहली बार भाजपा विधायक बने बिष्णु प्रसाद शर्मा ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कोलकाता स्थित टीएमसी मुख्यालय में शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और उद्योग मंत्री शशि पांजा ने उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल कराया। पार्टी बदलते ही शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उनके गोरखा भाई-बहनों ने चुना था, लेकिन भाजपा के झूठे वादों के कारण वे उनके लिए कुछ नहीं कर सके।

गोरखालैंड की मांग और भाजपा से पुरानी बगावत

बिष्णु प्रसाद शर्मा हमेशा से ही अलग गोरखालैंड और उत्तर बंगाल राज्य की मांग के मुखर समर्थक रहे हैं। इस मांग पर कोई ठोस कदम न उठाने के कारण वे पहले भी कई बार अपनी पुरानी पार्टी भाजपा की खुलकर आलोचना कर चुके हैं और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी में अहम रोल

गगनयान मिशन के ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन टेस्ट सफल

एजेंसी । चंडीगढ़

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' ने सफलता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। गगनयान के लिए इस्तेमाल होने वाले 'ड्रोग पैराशूट' का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस अहम परीक्षण के दौरान पैराशूट पर अधिकतम उड़ान भार से भी ज्यादा लोड डालकर उसकी मजबूती और सुरक्षा मार्जिन की बारीकी से जांच की गई।

चंडीगढ़ की विशेष RTRS सुविधा में हुआ परीक्षण

यह डायनेमिक परीक्षण बुधवार (18 फरवरी) को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) की अत्याधुनिक 'रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड' (RTRS) सुविधा में किया गया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की स्पेशल हाई-स्पीड एयरोडायनेमिक और बैलिस्टिक मूल्यांकन सुविधा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

ISRO और DRDO का शानदार संयुक्त प्रयास

इस जटिल परीक्षण को सफल बनाने में देश के कई प्रमुख विज्ञान संस्थानों ने मिलकर काम किया। इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC), DRDO की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ADRDE) और TBRL की टीमों ने अहम भूमिका निभाई। बता दें कि इससे पहले 24 अगस्त 2025 को भी स्पेस से वापसी के क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया जा चुका है।

स्वदेशी डिजाइन और क्षमता पर लगी मुहर

इस टेस्ट के सफल होने के बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि भारत मजबूत और बड़ी क्षमता वाले रिबन पैराशूट को खुद डिजाइन करने और बनाने में सक्षम है। यह सफलता इस बात की भी पक्की गारंटी देती है कि गगनयान मिशन के दौरान जब असली और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सामने आएंगी, तब भी यह पैराशूट पूरी तरह सुरक्षित और सटीक रूप से अपना काम करेगा। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने में इस ड्रोग पैराशूट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी।

विशेषाधिकार विभाग ने कांग्रेस को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। एआई इंपैक्ट समिट के बीच लोकसभा विशेषाधिकार विभाग ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एक एआई वीडियो को लेकर कांग्रेस के मीडिया विभाग को नोटिस जारी किया है। भाजपा सांसद विष्णु दत्त शर्मा की शिकायत पर जारी किए गए इस नोटिस में तीन दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। लोकसभा के विशेषाधिकार विभाग ने कांग्रेस सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत, पार्टी महासचिव जयराम रमेश, पवन खेडा और संजीव सिंह सहित नौ पदाधिकारियों को नोटिस भेजा है। यह नोटिस अध्यक्ष के खिलाफ एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर भेजा गया है।

सुप्रिया ने नोटिस मिलने की पुष्टि की

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि हमने जवाब देने के लिए समय मांगा है। इसके साथ उन्होंने सवाल किया कि सदन में भाषण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष को बहुत कम समय के लिए टीवी पर दिखाना विशेषाधिकार का उल्लंघन है या नहीं। श्रीनेत ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब पर बोलना चाहते थे।